



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

10/9/02

सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2002/फाल्गुन 9, 1923

No. 51]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2002/PHALGUNA 9, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2002

फा. सं. 2(5)-बी(डी)/2002.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2002-2003

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा का भाषण

28 फरवरी, 2002

भाग क

मान्यवर,

मैं वर्ष 2002-2003 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. सहस्राब्दि का यह पहला वर्ष 2001 अनेक दुःखद घटनाओं का साक्षी रहा है और अनेक चुनौतियों से पूर्ण रहा है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी को गुजरात के भूकंप से हुई थी और 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर आतंकवादी हमले, 11 सितम्बर को अमरीका की घटना और एक अक्टूबर को श्रीनगर की नृशंस घटना के साथ इसका समापन हुआ। मैं सुरक्षा बलों के उन बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस संसद की रक्षा की और महान बलिदान किया। आर्थिक मोर्चे पर भी यह एक कठिन वर्ष रहा है। लगातार सात वर्षों की उच्च वृद्धि के बाद 2001 में विश्व आर्थिक वृद्धि कम होकर 2.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भयंकर आतंकवाद और साथ ही साथ भूमंडलीय आर्थिक मंदी गत वर्ष की सर्वाधिक दुःखद विशेषता रही है।

आर्थिक परिदृश्य

3. प्रतिकूल आर्थिक एवं सुरक्षा परिवेश के बावजूद अर्थव्यवस्था का निष्पादन इस वर्ष अपेक्षतया अच्छा रहा है। पिछले दो वर्षों के अनियमित मानसून के बाद इस वर्ष के अपेक्षाकृत अच्छे मानसून के कारण कृषि की स्थिति में सुधार हुआ। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि लगभग 5.4 प्रतिशत होने की आशा की जाती है क्योंकि उच्चतर वृद्धि औद्योगिक मंदी के कारण बाधित रही है। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व सुदृढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति दर गिरकर 1.1 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुँची है, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 50 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा पार कर गया है और हमारा खाद्यान्न भंडार बढ़कर लगभग 60 मिलियन टन पर पहुँच गया है। पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट ने समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को और राहत पहुँचाई है।

4. गद्यापि देश आर्थिक रूप से सुरक्षित है परंतु अर्थव्यवस्था को वृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनका विस्तृत उल्लेख 26 फरवरी को इस सदन के सामने प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में किया गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरा प्रयत्न एक बजट कार्यनीति तैयार करने का है।

बजट कार्यनीति

5. मैंने अपने पिछले बजट में आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी की एक व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की थी। मैंने कर सुधारों को भी व्यापक बनाया था जिनका उद्देश्य देश में आधुनिक कर प्रणाली प्रदान करना था। इस वर्ष मेरा उद्देश्य सभी स्तरों पर इन नीतियों को समेकित एवं कार्यान्वित करने का है। राज्य स्तर पर इस प्रक्रिया को सुधारों से संबद्ध लोक निधि व्यवस्था के द्वारा आगे बढ़ाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

6. अतः बजट की कार्यनीति इस प्रकार होगी :

- कृषि एवं खाद्य अर्थव्यवस्था सुधारों पर निरंतर जोर देना।
- आधारभूत सुविधाओं में सरकारी एवं निजी निवेश को बढ़ाना।
- वित्तीय क्षेत्रक एवं पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करना।
- संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाना और औद्योगिक वृद्धि उत्पन्न करना।
- गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कर सुधारों को सुदृढ़ करना और राजकोषीय समायोजन जारी रखना।

7. पिछले बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की वर्ष भर गहन रूप से मानीटरिंग की जाती रही है। पिछले वर्ष के बजट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के सामने रखने की प्रथा मैंने पिछले वर्ष शुरू की थी। तदनुसार मैं पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं : कृषि वस्तुओं पर नियंत्रण हटाना, चीनी पर नियंत्रण हटाने की दिशा में प्रगति, औषधियों के मूल्य नियंत्रण की अवधि में पर्याप्त कमी, रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम समाप्त करने सहित कंपनियों के पुनरुद्धार और/या उनको बंद करने से संबंधित विद्यमान कानून को संशोधित करने का निर्णय, निजीकरण में पर्याप्त प्रगति तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति तथा अतिरिक्त (सरप्लस) सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की घोषणा।

8. यह निर्णय आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आम लोगों तक यह लाभ पहुंचे। इसके लिए अच्छे कार्यान्वयन और प्रशासन की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए हम ऐसे उपाय करेंगे जिनका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना और अपने नागरिकों की जीवन दशाओं में सुधार लाना होगा।

कृषि और ग्रामीण विकास

अविनियमन

9. हरित क्रांति और उसके बाद श्वेत क्रांति में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद हमारा देश अब कृषि विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण की तीसरी क्रांति के लिए तैयार है। इसके लिए

नीति परिवर्तनो, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार पर नए सिरे से जोर देने और एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सके। इस नई क्रान्ति के लिए शेष विनियामक और प्रक्रियात्मक जटिलताएं जो अभी भी विद्यमान हैं, को हटाना तथा उन्नत ग्रामीण अवसंरचना अनिवार्य है। किसान की आजादी हमारी नीति का मूल लक्ष्य है।

10. यद्यपि कृषि राज्य का विषय है फिर भी केंद्र सरकार की अनेक नीतियां हैं जो इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की पुनरीक्षा की है। खाद्य एवं कृषि उत्पादों के भंडारण, विक्री और लाने ले जाने को रोकने वाले आदेशों को हटाया जा रहा है। अब हम कृषि उत्पादों के लिए देशव्यापी एकीकृत बाजार की आशा कर सकते हैं। इस पहल को जारी रखने के लिए मैं निम्नलिखित रूप से कृषि के संबंध में अनियंत्रण एवं अविनियमन का प्रस्ताव कर रहा हूं।

- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दशाओं का नियमन जारी रखते हुए नई दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता पर प्रतिबंध हटाने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश (एमएमपीओ) का संशोधन।
- विभिन्न कृषि उपस्कर मंदों से संबंधित लघु उद्योग आरक्षणों को हटाना।
- कृषि वस्तुओं के निर्यात को सारणीबद्धता से हटाना और शेष निर्यात नियंत्रण क्रमिक रूप से हटाना।
- सभी कृषि वस्तुओं को शामिल करने के लिये भावी और वायदा व्यापार का विस्तार।

11. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश, औद्योगिक मानक ब्यूरो और एम.एम.पी.ओ. के अधीन खाद्य मानकों के लिये अनेक विनियमों से खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रभावित है। इनके आधुनिकीकरण और एकीकरण की आवश्यकता है। एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून एवं संबंधित विनियमों को तैयार करने के लिए कानूनी और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक दल के गठन का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है।

12. किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करने की इस प्रक्रिया को अब राज्य सरकारों द्वारा आगे बढ़ाने की जरूरत है। संभावित प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे ही विक्री करने के लिए किसानों को समर्थ बनाने हेतु कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों के संशोधन से उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और संभावित नए बाजारों में पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ऐसे राज्य नियंत्रण आदेश जो अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए बाधक बने हुए हैं, को हटाने की आवश्यकता है। मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में अतिरिक्त आवंटनों को राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र के अनियंत्रण एवं अविनियमन से संबद्ध किया जाएगा।

13. वर्ष 2000-01 में मैंने शीत भंडारों के निर्माण के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शीत भंडारों में 21 लाख टन की क्षमता के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है जो 12 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल घोषित ग्रामीण गोदाम स्कीम भी प्रचालन में आ गई है। अनेक नियंत्रण आदेशों को हटाने से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत काफी अधिक निवेश होगा। तदनुसार मैं वर्ष 2002-03 में सब्सिडी संबद्ध प्रत्येक ऋण स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि ऋण

14. कृषि क्षेत्रक के लिए पर्याप्त ऋण मिलता रहे, इसके लिए वित्तमंत्री के रूप में अपने को मैं विशेष रूप से उत्तरदायी समझता हूँ। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस वर्ष सांस्थानिक माध्यमों से कृषि क्षेत्रक को मिलने वाले कुल ऋण का लक्षित स्तर 64,000 करोड़ रुपए होने की आशा है। वर्ष 2002-2003 में यह आशा की जाती है कि यह बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। कृषि ऋण की प्राप्ति में आगे सुधार के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

- ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ VIII) की धनराशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 5,500 करोड़ रुपए की जाएगी और व्याज दर 10.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत की जाएगी। आगे से यह दर विद्यमान बैंक दर + 2 प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। आरआईडीएफ से राज्यों को सहायता कृषि और ग्रामीण क्षेत्रकों में सुधारों से संबद्ध की जाएगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड : इन्हें वर्ष 1998-99 में शुरू किया गया था जिन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली और कृषि ऋण प्राप्त करने में हमारे किसानों को काफी मदद मिली है। 31 दिसंबर, 2001 तक 63 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रकार कुल 2.07 करोड़ कार्ड जारी हो चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड संबद्ध व्यक्तिगत बीमा पैकेज भी लागू कर दिया गया है।
- इसी तरह स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण स्कीम भी अच्छी चल रही है। चालू वर्ष के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूह का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है और 70 लाख परिवारों को शामिल करते हुए यह संख्या 3.5 लाख से अधिक पहुंच गई है जिससे विश्व में यह सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बन गया है। वर्ष 2002-2003 के लिए मैं यह लक्ष्य बढ़ाकर 1.25 लाख कर रहा हूँ।
- दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार 25,000 रुपए तक के बकाया मूलधन वाले छोटे ऋण खातों के लिए एकबारगी भुगतान की स्कीम पहले ही चालू है। छोटे और सीमांत कृषकों के लिए 50,000 रुपए तक के ऋणों को शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष एकबारगी भुगतान स्कीम की घोषणा की जाएगी।

फसल बीमा

15. राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम पहले से ही चल रही है। किसानों की आवश्यकताओं को बेहतर रूप से पूरा करने और सक्षम बीमांकित प्रणाली अपनाने के लिए मैं कृषि बीमा के लिए एक नए निगम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जिसे विद्यमान सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा चलाया जाएगा।

सिंचाई

16. मैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए इस वर्ष के 2000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 2800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राज्यों को अपनी अपूर्ण, गंध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और वह उपभोक्ता शुल्कों का रांशोधन तथा जल उपभोक्ता संघों की स्थापना के द्वारा सुधार कार्य भी कर सकेंगे।

कृषि विस्तार एवं अनुसंधान

17. कृषि के त्वरित विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं के संबंध में एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अतः मैं कृषि अनुसंधान के लिए वर्ष 2002-03 में चालू वर्ष के 684 करोड़ रुपए की तुलना में आबंटन बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। कृषि अनुसंधान के प्रशासन की संपूर्ण पुनरीक्षा का भी प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह प्रणाली सृजनात्मक रूप से नई आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

18. अनुसंधान एवं विस्तार प्रणालियों की गुणवत्ता एवं कारगरता सुधारने के लिए अनुसंधान एवं विस्तार के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, किसान संगठनों, सहकारिताओं, निगमित क्षेत्रक और कृषि व्यापार क्लिनिकों के माध्यम से विस्तार प्रणाली को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाएगा। जैविक उत्पादों, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशियों सहित गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया जाएगा। ऐसी सहकारिताओं/कंपनियों के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति, कृषि प्रसंस्करण एवं व्यापार को 'नाबार्ड' की सहायता से ऋण की उपलब्धता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001 पहले ही संसद में पेश कर दिया गया है ताकि विद्यमान उत्पादक सहकारी कारोबारों को कंपनियों में परिवर्तित किया जा सके।

कृषि निर्यात

19. कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दशायें उत्पन्न करने के लिए कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तक ऐसे 15 क्षेत्रों का अनुमोदन कर दिया गया है। इन कृषि निर्यात क्षेत्रों में आधार सुविधाओं के विकास में तेजी लाने एवं यूनिटों को ऋण प्रदान करने के लिये 'अपेडा' (कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) कार्य करेगा।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण सड़कें

20. हमारे सभी गांवों को सभी मौसमों में चालू सड़कों से जोड़ने के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी जिसमें काफी प्रगति हो रही है। अभी तक प्रदान किये गये 5000 करोड़ रुपए के अलावा वर्ष 2002-2003 के लिये 2500 करोड़ रुपए का और आवंटन किया जा रहा है। इन कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन को देखते हुए मेरा विचार अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाना है जिसमें वर्ष के दौरान बहुक्षेत्रीय स्रोतों से मिलने वाले संसाधन भी शामिल हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

21. अपने पिछले बजट भाषण के दौरान मैंने ऐसे 80,000 गांवों के विद्युतीकरण के लिये, जहां बिजली नहीं है, एक पैकेज की घोषणा की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिये ऋण चुकाना मुश्किल होता है, सरकार का प्रस्ताव त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू करने का है। वर्ष 2002-2003 में इस स्कीम के लिये 164 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

ग्रामीण रोजगार

22. वर्ष 2001 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गयी थी जिसके लिये चालू रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) को एक में मिला दिया गया था। इस स्कीम को आरंभ करने के समय से, राज्यों को आबंटित 50 लाख टन में से 30.6 लाख टन खाद्यान्न जारी करने हेतु पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। यह स्कीम अगले वर्ष भी जारी रखी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत दिये जा रहे मुफ्त खाद्यान्न का पूरा फायदा उठाने के लिये आगे आने हेतु मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूँ।

23. लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण को कमजोर वर्गों के लिये हमेशा विशेष चिंता थी। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिये मैं जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना (जे.पी.आर.जी.वाई.) शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन जिलों में रोजगार उत्पन्न करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिये मेरे साथी ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य-बल का गठन किया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, डी.सी. (लघु उद्योग) एवं अन्य एजेंसियों को पूर्ण रूप से इस स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।

24. खादी एवं ग्रामीण उद्योगों में क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ग्रामीण-औद्योगीकरण बढ़ाने में अत्यधिक मदद मिलेगी। इस प्रयत्न में सहायता करने के लिये मैं 1935 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये वर्धा संस्थान का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नयन का प्रस्ताव करता हूँ जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान कहा जाएगा।

25. बाजार में बिक्री के लिये समुचित आधार सुविधाओं के बिना कृषि का विविधीकरण सफल नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे.जी.एस.वाई.) नामक विशेष स्कीम के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर ग्रामीण उत्पाद विपणन केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना तथा ग्रामीण हाटों को उन्नत बनाने के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों, सहकारिताओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाएगी।

26. हमारे देश के कुछ हिस्से प्राकृतिक आपदाओं से विशेष रूप से ग्रस्त हैं। प्रभावित राज्यों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 480 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। ऐसे संकटापन्न क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत गरीबों द्वारा बनाये गये मकानों के लिये अब आगे से मास्टर पालिसी के जरिये बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

खाद्य-अर्थव्यवस्था का प्रबंधन

27. भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं एवं चावल की उगाही के अभूतपूर्व स्तर और पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक की काफी कम आवश्यकता के बीच बढ़ते हुए अंतर से उत्पन्न गंभीर नीति एवं राजकोषीय कठिनाइयों की ओर पिछले वर्ष मैंने ध्यान आकर्षित किया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऊंची कीमतों पर उगाही एवं भारी सब्सिडी वाली कीमतों पर बिक्री की वर्तमान स्थिति चल सकने योग्य नहीं है। विकेन्द्रीकृत उगाही की अवधारणा को अभी तक राज्यों का सहयोग नहीं मिला है। दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन हेतु हम स्थायी उपाय तैयार करेंगे।

28. खाद्यान्न के भारी रटौक को कम करने के लिये, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं, जो भण्डारण एवं विक्री की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं : गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये अधिक आवंटन, एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत कार्य प्रोग्राम के लिये अधिक खाद्य जारी करना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये राज्यों को 30 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन, वर्ष 2000-01 में 5.5 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 30 लाख टन की खुले बाजार में विक्री और खाद्यान्न निर्यात के लिये अधिक प्रोत्साहन।

आधारभूत सुविधायें

29. हमारी विकास की आकांक्षाओं के लिये कुशल एवं विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण है। निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने के लिये उचित उपभोक्ता शुल्क लगाने का महत्वपूर्ण मुद्दा बार बार आता है। दूर संचार, सड़क एवं पत्तन जैसे क्षेत्रों में जहां उचित उपयोगकर्ता शुल्क विद्यमान है, कुछ सफलता प्राप्त की गई है। मेरे सहयोगी रेल मंत्री द्वारा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने और अन्य किये गये साहसिक उपायों से हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में रेलवे देश की महत्वपूर्ण परिवहन की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा। विद्युत, शहरी आधारभूत सुविधाओं, परिवहन एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में समुचित उपयोगकर्ता शुल्क के अभाव के कारण निरंतर बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है।

विद्युत

30. विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सक्षमता की बहाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी राज्य विद्युत बोर्डों के मामले में प्रतिफल की औसत दर लगभग ऋणात्मक 40 प्रतिशत है और उनकी सम्मिलित घाटे बढ़ते जा रहे हैं। अतः अकेले विद्युत क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन के लिए भी यह एक बड़ी चुनौतियों में से एक है।

31. इन गंभीर समस्याओं को समझते हुए, प्रधान मंत्री ने 3 मार्च, 2001 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक सक्षमता प्राप्त करने के लिये विद्युत क्षेत्र के सुधारों की आवश्यकता पर व्यापक सहमति प्रकट करते हुए सम्मेलन ने विद्युत वितरण सुधार और उसकी चोरी समाप्त करने पर विशेष जोर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य मंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त दल ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं कर मुक्त बाण्ड जारी करने के द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की उपयोगी सेवाओं के लिये राज्य विद्युत बोर्डों की अतिदेय बकाया राशियों के संबंध में एक बार में भुगतान की सहमति दी थी वशर्ते विनिर्दिष्ट निष्पादन मानदण्ड प्राप्त कर लिया गया हो और भविष्य में वर्तमान देयताओं का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित हो। मैं राज्यों से आगे आने और शीघ्रता से स्कीम का कार्यान्वयन करने का आग्रह करता हूँ।

32. विद्युत मंत्रालय ने 20 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिये हैं और शेष राज्यों के साथ शीघ्र ही यह कार्यवाई पूरी होने की आशा है। इस दिशा में अपने प्रयत्नों को दुगुना करने के लिये ए.पी.डी.पी. को तीव्रीकृत विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के रूप में पुनः तैयार किया जा रहा है जिसके लिये योजना आवंटन इस वर्ष 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2002-03 में 3500 करोड़ रुपए किया जा रहा है। राज्यों के लिये निधि की उपलब्धता सहमतिपूर्ण सुधार कार्यक्रम के आधार पर होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति की यूनिट लागत और विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर राजस्व वसूली के बीच अन्तर को कम करना और अंततः उसे समाप्त करना होगा। तदनुसार सुधार का केन्द्र विन्दु उत्पादन से संप्रेषण एवं वितरण में परिवर्तित कर दिया गया है।

33. एक उच्च स्तरीय मानिट्रिंग ग्रुप इस कार्यक्रम की प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा। विद्युत वित्त निगम से रियायती शर्तों पर ऋण के द्वारा इस कार्यक्रम के लिये आबंटन बढ़ाया जाएगा।

सड़कें

34. मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि तीन वर्ष पहले शुरू किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) अच्छी प्रगति कर रहा है। अब मैं सड़क क्षेत्रक में पूर्णतः नये परिदृश्य को प्राप्त करने का आश्वासन देता हूँ। स्वर्ण चतुर्भुज दिसम्बर, 2003 तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जाएगा जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले है। उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कारिडोर की लंबाई 7300 कि. मी. है जिसमें से 716 कि.मी. को पहले ही चार लेन वाला बना दिया गया है। अनेक पक्षों से निधिपोषण, सरकारी गारंटी के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अन्य उधारों और अन्य नई वित्तपोषण स्कीमों की सहायता से इस चरण की निधि व्यवस्था को 2002-03 में पूर्णतः सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

पत्तन

35. पत्तन न्यास संरचना भारतीय बड़े पत्तनों में लचीलेपन को प्रदान नहीं करती जो कुशल प्रबंधन और सांस्थानिक निधि व्यवस्था जुटाने के लिए आवश्यक है। अतः बड़े पत्तनों का चरणबद्ध तरीके से निगमीकरण करने का प्रस्ताव किया जाता है। निजी क्षेत्रक के निवेशों की सुविधा प्रदान की गई है और 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य 8 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। विद्यमान पत्तनों के निगमीकरण और नए निजी क्षेत्रक के पत्तनों के बनने से विनियामक संरचना सुदृढ़ हो जाएगी।

नागर विमानन

36. सरकार ने निजी क्षेत्रक के प्रबंध और दीर्घकालिक पट्टा प्रणालियों के माध्यम से निवेश को शुरू करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को उन्नत करने के अपने निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है। बोलियां आमंत्रित करने की कार्यपद्धति को अंतिम रूप से दिया गया है और पट्टेदारी की प्रक्रिया 2002-03 में पूरी हो जाएगी।

37. निम्नलिखित रियायतों के द्वारा ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा:

- राज्य सरकार से भूमि एवं संबंधित आधार सुविधाओं की उपलब्धता;
- केन्द्रीय विक्री कर दर से विमानन टर्बाइन ईंधन पर विक्री कर लगाने वाले राज्यों में स्थित परियोजनाओं के संबंध में बाहर जाने वाले यात्रियों पर अंतर्देशीय विमान यात्रा कर और विदेशी यात्रा कर लगाने से छूट;
- ग्रीनफील्ड (संभावित विकास क्षमता वाले) विमानपत्तन के वित्तपोषण में सहायता के लिए विद्यमान विमानपत्तनों पर अतिरिक्त यात्री सेवा शुल्क के रूप में अग्रिम विकास शुल्क लगाना;
- नए विमान पत्तनों पर उपभोक्ता विकास शुल्क लगाना;
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता/इक्विटी भागीदारी;

बंगलौर और हैदराबाद के प्रस्तावित नए विमान पत्तनो को इन रियायतों से लाभ मिलेगा।

शहरी विकास

38. वर्ष 2001 की जनगणना यह प्रदर्शित करती है कि भारत की शहरी आबादी अब लगभग 285 मिलियन है जो संयुक्त राज्य की कुल आबादी से अधिक है। एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों की संख्या 1991 में 23 से बढ़कर 2001 में 35 हो गई है। हम अपने अधिकांश कस्बों और शहरों की दुर्दशा के बारे में जानते हैं। यदि इन्हें विकास के इंजन के रूप में कार्य करना है और अपने नागरिकों को उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है तो इनकी हालत बदलने की जरूरत है। अतः इस क्षेत्र में सुधारों में विलंब नहीं होना चाहिए।

39. राज्यों को सुधारों से संबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए मैं 500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। यह निधि निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों को प्रोत्साहित करेगी:-

- किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार और शहरी भूमि हदबंदी कानूनों को रद्द करना।
- उच्च स्टाम्प शुल्क प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
- भवन निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उप-नियमों में संशोधन।
- शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल कानून के अनुरूप नगरपालिका कानूनों में संशोधन।
- कृषि वाली भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने हेतु कानूनी एवं प्रक्रियात्मक ढांचों का सरलीकरण।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शुल्क लगाना और संसाधन जुटाना।
- नागरिक सेवाओं के प्रावधान में सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करना।

40. एक प्रोत्साहन आधारित सुविधा के रूप में शहर चुनौती निधि (सीसीएफ) की भी स्थापना की जाएगी जो नगरपालिका प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने की सक्षम एवं विश्वसनीय सांस्थानिक प्रणालियों की दिशा में चलने की संक्रमण लागत के निधि पोषण के लिए शहरों को सहायता प्रदान करेगी। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय रूप से सक्षम परियोजनाओं को विकसित करने की लागत के आंशिक वित्तपोषण में सहायता प्रदान करेगी। उधार पात्रता आधार पर बाजार उधार प्राप्त करने में स्थानीय निकायों की सहायता हेतु ऋण बढ़ाने के लिए एक समूह वित्त विकास स्कीम स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है। उधार के पात्र बनने और शहरी आधार सुविधाओं में निवेश करने के योग्य बनने के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु और प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, मैं इस वर्ष 200 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 500 करोड़ रुपये तक के नगरपालिका कर मुक्त बांडों को जारी करने का प्रावधान कर रहा हूँ।

पर्यटन

41. देशी पर्यटन के जरिये रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा प्राप्ति और अधिक राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में अपने लाभकारी प्रभाव को देखते हुए पर्यटन एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। अतः निम्नलिखित व्यापक पर्यटन विकास पैकेज को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया जाता है :

- वर्ष 2002-2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए 6 पर्यटन सर्किटों का पता लगाया जाएगा।

- इन सर्किटों में आधार सुविधा विकास के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रक दोनों से संसाधन जुटाने हेतु विशेष प्रयोजन वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी।
- एक विशेष क्षेत्र के रूप में हम्पी के विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरिटेज) स्थल को एकीकृत मास्टर प्लान पर आधारित पर्यटन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

42. तदनुसार, पर्यटन के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2002-2003 में 50 प्रतिशत बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर्यटन के संबंध में राजकोषीय उपायों पर मैं अपने भाषण के भाग “ख” में अधिक उल्लेख करूंगा।

आधार सुविधाओं का वित्तपोषण

43. सरकारी निवेश की अनुपूर्ति के लिए आधार सुविधा क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक के निवेश को आकर्षित करने के लिए हमारे द्वारा किए गए निरंतर प्रयत्नों की सदस्यों को जानकारी है। परन्तु दूरसंचार क्षेत्रक को छोड़कर निवेश प्राप्ति की गति मंद रही है। अतः मैं आधार सुविधाओं में तेजी से निजी निवेश को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

- आधार सुविधा परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश प्रदान करने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक आधार सुविधा इक्विटी निधि की स्थापना की जाएगी। आधार सुविधा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) द्वारा व्यवस्था की जाने वाली इस निधि के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा प्रारंभिक अंशदान किया जाएगा।
- 250 करोड़ रुपए से अधिक की आधार सुविधा परियोजनाओं के ऋण वित्तपोषण को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा समन्वित करने के लिए एक सांस्थानिक कार्यप्रणाली स्थापित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रकों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व की साझेदारी आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. के साथ करते हुए आईडीएफसी एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए एक कार्यबल द्वारा कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।

लोक-निवेश

44. महत्वपूर्ण आधार सुविधा क्षेत्रकों में लोक निवेश को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। विद्युत, राजकों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेलवे में आंतरिक एवं वजट-बाह्य संसाधनों सहित योजना परिव्यय क्रमशः 22 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, जो कुल 37919 करोड़ रुपए है।

वित्तीय क्षेत्रक और पूंजी बाजार

ऋण बाजार

45. सामान्य रूप में एक पारदर्शी एवं सक्रिय ऋण बाजार और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए पिछले वर्ष किए गए प्रस्तावों पर अच्छी प्रगति हुई है। एक इलेक्ट्रॉनिक सौदा तय प्रणाली (एनडीएस) द्वारा अब सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन को सरल बनाया जा रहा है और नए क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार की कार्यकुशलता बढ़ाई जा रही है। निवेशकों को अपने निवेशों की बेहतर योजना बनाने तथा बाजार में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर की घोषणा करेगा। अब सभी राज्य विधानसभाओं से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् मैं भी संसद के इसी सत्र के दौरान पुराने सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1949 को एक नए सरकारी प्रतिभूति विधेयक से प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पूँजी बाजार

46. पूँजी बाजार में घटित विभिन्न बाधा पैदा करने वाले घटनाक्रमों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ाया जाए और बाजार की निष्ठा को मजबूत किया जाए। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

- स्टाक एक्सचेंजों के पृथक् स्वामित्व, प्रबंध और प्रचालन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों के पृथक् स्वामित्व और निगमीकरण की प्रक्रिया इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने स्टाक एक्सचेंजों में प्रबंधन पदों पर दलाली सदस्यों के प्रवेश पर पहले ही रोक लगा दी है।
- निवेशकों की सुरक्षा तथा पूँजी बाजार के विनियामक के रूप में 'सेबी' की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए संसद के बजट सत्र के दौरान 'सेबी' अधिनियम, 1992 में कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा।
- लेखा संबंधी मानकों और लेखा-परीक्षकों की प्रभावकारिता के संबंध में विदेशों में और देश के भीतर हुए घटनाक्रम को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र के विनियमन को मजबूत बनाया जाए।
- विदेशी सांस्थानिक निवेशक पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के अधीन किसी कंपनी में एक विशेष संकल्प के तहत शेयरधारकों के सामान्य निकाय के अनुमोदन से कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 24 प्रतिशत से अधिक का निवेश कर सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब विदेशी सांस्थानिक निवेशकों का पोर्टफोलियो निवेश विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये क्षेत्रकीय सीमाओं के अधीन नहीं होगा। इस संबंध में अलग से मार्ग निर्देश जारी किये जायेंगे।

47. पूँजी बाजार के विकास और इसे गहन बनाने के लिए कुछ और उपाय किए गए हैं:

- बदला व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और व्यावहारिक रूप में अब स्टाक व्यापार चल निपटान प्रणाली के रूप में किया जा रहा है।
- एक्सचेंज द्वारा व्यापार किए जाने वाले व्युत्पन्न अब व्यापक हो गये हैं जिसके अंतर्गत नकदीकरण के लिए विकल्प के रूप में बहुत से लिखत उपलब्ध हैं।
- जुलाई, 2001 में व्यक्तिगत स्टाक विकल्पों और सूचीबद्ध स्टाक विकल्पों की शुरुआत तथा नवम्बर, 2001 में एकल स्टाक भावी सौदों की शुरुआत की गई थी।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब विनिर्दिष्ट व्यापारिक सीमाओं के भीतर सभी स्टाक व्यापार व्युत्पन्न उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- दावा न की गई और भुगतान न की गई राशियों को जमा करने के लिए 1 अक्टूबर, 2001 से एक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि की स्थापना की गई है।

48. यू एस-64 स्कीम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट में सुधार लाने के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है जिसका प्रयोजन प्रणालीगत सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के हितों का सामंजस्य बनाए रखना है। यूएस-64 को एनएवी आधारित बनाने के लिए काफी समय से लम्बित सुधार को क्रियान्वित कर दिया गया है। यूटीआई अधिनियम में आगे विधायी परिवर्तन लाने के लिए वर्ष के दौरान अन्य आवश्यक सुधार उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं।

बैंकिंग क्षेत्र

49. बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधार इस क्षेत्र की कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु जारी रहेंगे। निम्नलिखित उपाय किए गये हैं या किए जा रहे हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वर्ष में वसूल किए गए 9,883 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2000-01 में 12,860 करोड़ रुपए की वसूली की और निवल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां पिछले वर्ष की 7.4 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार घटकर 6.7 प्रतिशत हो गयीं।
- 29 कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों तथा 5 अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना की गयी। 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार, कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों ने 18703 मामलों का निपटान किया जिनमें 14,026 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। 3,527 करोड़ रुपए की वसूली की गयी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अपेक्षित गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिये प्रावधान करने हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय राहत दी जा रही है जिसका व्यौरा मेरे भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है। इससे बैंक अपनी उधार दरों की समीक्षा करने में समर्थ होंगे।
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के मोचन निषेध और प्रवर्तन के माध्यम से ऋणदाता को मजबूती प्रदान करने हेतु, संसद में बैंकिंग क्षेत्र सुधार सम्बन्धी एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक दीर्घकालिक ऋणों में रुद्ध पूंजी के सम्बन्ध में प्रतिभूतिकरण को भी सक्षम बनाएगा।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की भागीदारी से 30 जून, 2002 तक एक प्रायोगिक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी की स्थापना की जाएगी। यह कम्पनी बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों को ग्रहण करने हेतु उपाय करेगी और प्रतिभूतिबद्ध ऋणों से सम्बद्ध बाजार का विकास करेगी।
- जमा बीमा ऋण तथा गारंटी निगम को बैंक जमा बीमा निगम में रूपान्तरित किया जाएगा ताकि इसे वित्तीय क्षेत्र में जमाकर्ताओं के जोखिमों से निपटने हेतु और संकटग्रस्त बैंकों के बारे में एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त विधायी परिवर्तन प्रस्तावित किए जाएंगे।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधारों ने आईडीबीआई जैसी विकास वित्त संस्थाओं के लिए नयी चुनौतियां पेश की हैं। आगामी वर्ष के भीतर आईडीबीआई का निगमीकरण करने हेतु विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे उपयुक्त गतिशीलता प्रदान की जा सके। इस बीच आईडीबीआई के श्रेणी-एक पूंजी को मौजूदा आईबीआरडी के रूपांतरण द्वारा मजबूती प्रदान की जा रही है और एनआईसी (एलटीओ) ऋणों को उपयुक्त दीर्घकालिक लिखतों में बदला जा रहा है।

- वर्ष 2000 में कम्पनी अधिनियम, 1956 में किए गए कतिपय संशोधनों के परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा कुछ चूकों के मामले में निदेशक चयन हेतु अयोग्य हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के नामित निदेशकों को इस उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों को वर्ष 1997-98 में गठित बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति द्वारा सुझाए गए मानदंड के आधार पर कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नामक दो बैंकों की स्थिति में सुधार आया है और उन्होंने लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि इंडियन बैंक में सुधार दिखाई दिया है लेकिन इसके पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कमी रही है। मॉनीटर योग्य सुधार उपायों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर इस बैंक के लिए पुनः पूंजीकरण सहायता प्रदान करने हेतु 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

50. बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली शाखाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति से कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी बैंकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे या तो अपने मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करें या सहायक बैंकों के रूप में अपनी स्थापना करें। किसी भी विदेशी बैंक को दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा। ऐसे सहायक बैंको को सभी बैंकिंग विनियमों का पालन करना होगा जिसमें अन्य स्वदेशी बैंकों के संबंध में लागू प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने वाले मानदंड भी शामिल होंगे। ऐसी सहायक कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत के मतदान के अधिकार की अधिकतम उच्च सीमा में छूट प्रदान करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

51. कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, सहकारी ऋण संरचना के पास कम पूंजी पर्याप्तता तथा उच्च गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां हैं, इसलिए उसमें सुधार करने की तुरन्त आवश्यकता है। मैंने इसकी कार्यप्रणाली की निकटता से जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के अधीन एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुख्यमंत्रियों तथा मेरे सहयोगी श्री विखे पाटिल की अध्यक्षता में गठित सहकारिता मंत्रियों की संयुक्त समिति द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी है। मॉडल सहकारी अधिनियम को अपनाने, राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को हटाने, चुनावों का समय पर आयोजन, सदस्यों की बड़ी भागीदारी, प्रबन्धन का व्यावसायीकरण आदि जैसे सुधार उपायों की सिफारिश की गयी है। केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 60 : 40 के अनुपात में सदस्यों की शेयर पूंजी में बढ़ोतरी करने के साथ पुनः पूंजीकरण फार्मूले का सुझाव दिया गया है। राज्यों को विचार करके निधिकरण के अपने हिस्से को स्वीकार करना होगा तथा सुधार के लिए सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करना होगा। हालांकि, यह विषय राज्य का है लेकिन भारत सरकार इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए हर संभव सहायता करेगी। इस प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान कर रहा हूँ तथा सुधार की गति को देखते हुए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा।

आवास वित्त

52. पिछले चार वर्षों में आवास वित्त के संबंध में किए गए प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। वर्ष 2000-2001 में आवास वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा किया गया कुल संवितरण 26,300 करोड़ रुपए था जो वर्ष में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। इस राशि ने लगभग 28 लाख मकानों के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था उपलब्ध करायी जो 20 लाख मकानों के वार्षिक लक्ष्य से काफी अधिक है। चालू वर्ष में, इस वृद्धि दर के लगभग 35 प्रतिशत पहुंच जाने की आशा है। आवास वित्त को और सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप, इस बैंक ने आवास ऋणों के प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है तथा यह बंधकों के मोचन निषेध का संचालन कर रहा है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक एक बंधक ऋण गारंटी स्कीम प्रारंभ करेगा जिसे सभी आवास ऋणों के संबंध में मुहैया कराया जाएगा जिससे ऋणदाताओं की चूक के विरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। यह आवास ऋणों को और अधिक समर्थनीय बनाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण की पहुंच में भी बढ़ोतरी होगी।
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम के अधीन लक्ष्य को चालू वर्ष में 1.7 लाख से वर्ष 2002-2003 के लिए 2.25 लाख तक बढ़ाना प्रस्तावित है। दिसंबर, 2001 तक लगभग 1 लाख इकाइयों का वित्तपोषण किया जा चुका है।
- इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटन को 13 प्रतिशत बढ़ाकर 2002-03 के लिए 1725 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

मैं आवास पर अपने भाषण के भाग 'ख' में और अधिक उल्लेख करूंगा।

पूँजी खाता उदारीकरण

53. पूँजी खाता परिवर्तनीयता कुछ समय से हमारी कार्यसूची में रही है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में हुई कई अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं सावधानी के साथ अपनी उदारीकरण की नीति जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, मैं पूँजी खाते को और उदार बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- अनिवासी भारतीयों के लिए जमा स्कीमों की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी। मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर(बी)) स्कीम और अनिवासी बाह्य रुपया (एन.आर.ई.) स्कीम प्रत्यावर्तनीय बनी रहेगी।
- अनिवासी भारतीयों को पूर्णतः परिवर्तनीयता प्रदान नहीं करने वाली स्कीमों को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाते में मौजूदा शेष को परिपक्वता पर परिवर्तनीय अनिवासी बाह्य रुपया खाते में जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- अनिवासी भारतीय भारत में किराए, लाभांश, पेंशन, ब्याज और इसके समान अन्य अपने वर्तमान अर्जनों को उपयुक्त प्रमाणन के आधार पर विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अब 50 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा से अधिक, स्वचालित मार्ग के माध्यम से वार्षिक आधार पर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती हैं।

- बाजार खरीद द्वारा विदेश में संयुक्त उपक्रमों में समुद्रपारीय निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से अधिक अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसा किसी पूर्वानुमोदन के बिना कर सकती हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अच्छे निष्पादन रिकार्ड वाले कार्पोरेट्स को विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं में चेयर्स की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपायों जिनसे विदेश में समुदाय को लाभ मिलने की संभावना हो, के लिये अपनी विदेशी मुद्रा आय से निधियों में अंशदान की अनुमति दी जाएगी।
- भारतीय म्युचुअल फंडों को अब मौजूदा सीमाओं में पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्राओं वाले देशों में मूल्यबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पहले ऐसे निवेश की अनुमति समुद्रपारीय बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में ही दी जाती थी।
- विदेशी वाणिज्यिक उधारों का पूर्व-भुगतान ईईएफसी खाते में उपलब्ध शेष की सीमा, जो इस समय निर्यात आय के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, तक अनुज्ञेय है। विदेशी वाणिज्यिक उधार धारकों की निम्न ब्याज दरों से लाभ उठाने योग्य बनाने के लिए निर्यात आय से उच्चतर राशि के उपयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।
- पूंजी खाता लेन-देनों को और उदार बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्ड (एफसीसीबी) स्कीम को 50 मिलियन अमरीकी डालर तक स्वचालित मार्ग के अधीन रखने का प्रस्ताव किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक इन उपायों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी करेगा।

54. जहां पूंजी खाते का उदारीकरण आवश्यक है वहीं हमें गैर कानूनी पूंजी प्रवाहों को रोकने में सावधानीपूर्वक सतर्कता बरतनी होगी। हाल ही में देखे गये प्रमाण देश में आतंकवादी गतिविधियों की सहायता के लिए विभिन्न माध्यमों से बड़ी राशियों के अंतरण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सरकार आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध वित्तीय लेन-देनों से सम्बद्ध संभावित हवाला आपरेटरों/अवैध रूप से मुद्रा का लेन-देन करने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार देने के लिए संसद के वर्तमान सत्र के दौरान एक उचित विधान लाने का प्रस्ताव करती है।

संरचनात्मक सुधार

पेट्रोलियम के लिए प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम)

55. नवम्बर, 1997 में सरकार द्वारा जैसा निर्णय लिया गया और पिछले वर्ष मेरे द्वारा दोहराया गया था, मैं पहली अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्रक में प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- तेल पूल खाते को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा और बकाया शेष का समापन संबंधित तेल कंपनियों को ऑयल बाण्ड जारी करके किया जाएगा।

- निजी कंपनियों को निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन वितरण की अनुमति दी जाएगी।
- क्षेत्रक का निरीक्षण करने के लिए एक पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड गठित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर में रिफाइनरियों को सब्सिडी युक्तिसंगत आधार पर जारी रहेगी।
- दूरस्थ क्षेत्रों में एलपीजी और मिट्टी के तेल के लिए मालभाड़ा सब्सिडी जारी रहेगी।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, डीजल का मूल्य प्रति लीटर लगभग 50 पैसे और पेट्रोल का मूल्य लगभग 1 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगा। मूल्यों में यह परिवर्तन प्रारंभिक रूप से तेल पूल खाते के भाग के रूप में 1 मार्च, 2002 से लागू होगा।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने पर वर्ष 1997 में लिए गए सरकार के निर्णय ने एलपीजी और मिट्टी के तेल पर पहली अप्रैल, 2002 तक सब्सिडी क्रमशः 15 और 33 प्रतिशत कम करने का अधिदेश दिया। तदनुसार, 1 मार्च, 2002 से एलपीजी का मूल्य प्रति सिलेंडर लगभग 40 रुपए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल का मूल्य लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जा रहा है। ये सब्सिडियां 1 अप्रैल, 2002 से समेकित निधि द्वारा वहन की जाएंगी।
- एलपीजी और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी पहली अप्रैल, 2002 से निर्दिष्ट एक समान दर पर होगी। खुदरा मूल्य तब अंतराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में परिवर्तन के साथ भिन्न-भिन्न होगा।
- इन सब्सिडियों को आगामी 3 से 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली-पश्च उत्पाद और सीमाशुल्क परिवर्तन का विवरण भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है। चूंकि सब्सिडी के बोझ का वहन केन्द्रीय बजट द्वारा अगले वर्ष से किया जाएगा इसलिए अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिए कराधान उपाय तैयार किये गए हैं।

56. मुझे विश्वास है कि प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के लिए उपायों का यह पैकेज उपभोक्ताओं और उत्पादकों की आवश्यकताएं पूरी करेगा। यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण भी सृजित करेगा।

57. प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के और ब्यौरे अलग से मेरे सहयोगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा घोषित किए जाएंगे।

औद्योगिक पुनर्संरचना

58. प्रतिस्पर्धा की ताकतों से निपटने के लिए औद्योगिक और अन्य कंपनियों को लगातार आधार पर पुनर्संरचना करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय पुनर्संरचना के कानूनी अवसरों के प्रयोग के अतिरिक्त व्यवहार्य संगठनों की सामाजिक और पारदर्शी निगमित ऋण पुनर्संरचना के लिए न्यायालय से बाहर की कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन निगमित ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) की कार्यप्रणाली स्थापित की गई है। मैंने इसके प्रचालन को और सक्षम बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में बैंकों और अन्यो वाला एक छोटा दल गठित करने का निर्णय लिया है।

59. मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में इस्पात और वस्त्र जैसे कुछ मुख्य उद्योगों के सुदृढीकरण के लिए विशिष्ट राजकोषीय उपाय तथा विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य उपायों की व्यवस्था करूंगा।

लघु उद्योग

60. जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, लघु उद्योग अब व्यापार उदारीकरण के पूरा होने से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के अधीन हैं। इसलिए, लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए एक नया दृष्टिकोण पहले ही अपनाया जा चुका है।

61. लघु क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह अनिवार्य है। लघु उद्योगों के पास निवल बैंक ऋण बकाया 31 मार्च 2000 को 45,789 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2001 को 48,445 करोड़ रुपए हो गया है। ऋण का प्रवाह और बढ़ाने के लिए:-

- मिश्रित ऋणों की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
- 30 सितंबर, 2001 तक लघु उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 391 विशिष्ट शाखाएं खोली गई हैं।
- संपार्श्विक जमानत की छूट सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अधीन परियोजना लागत सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है।
- लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना, ऋण गारंटी स्कीम और प्रौद्योगिकी उन्नयन की ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जा चुका है।
- किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से प्रोत्साहित होकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अब छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों, व्यावसायिकविदों और लघु क्षेत्रक वालों सहित स्व-रोजगार प्राप्त अन्य व्यक्तियों को सरलीकृत और उधारकर्ता अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी) स्कीम' नामक एक स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है।

62. सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले वर्ष मैंने जूते, चमड़े की सामग्रियों और खिलौना क्षेत्रों में 14 मदों के अनारक्षण की घोषणा की थी। सरकार आरक्षित सूची में कतिपय अन्य मदों के संबंध में पणधारियों के साथ विचार-विमर्श में लगी रही है। बुने हुए वस्त्रों, कतिपय कृषि उपकरणों, मोटरवाहन (ऑटो) संघटकों, कुछ रसायनों और औषधियों की 50 से अधिक मदों और अन्यो को अब अनारक्षित कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी, लघु उद्योग मंत्री अलग से इन मदों का व्यौरा घोषित करेंगे।

निर्यात

63. निर्यात के संवर्धन की गति को तेज करने के लिए सरकार हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। एक मुख्य नई पहल विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना करना है। मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में एसईजेड के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा करूंगा।

64. नए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों और संबद्ध सुविधाओं के सृजन द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस स्कीम के परिव्यय को

इस वर्ष 97 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 के लिए 330 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2002-2003 के लिए वाणिज्य विभाग का संपूर्ण परिव्यय 55 प्रतिशत बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए किया गया है।

मानव विकास

शिक्षा

65. संविधान के 93वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया है। इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। तदनुसार, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग का आयोजना आवंटन इस वर्ष 4000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 के लिए 4900 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

66. पिछले वर्ष मैंने भारत और विदेश में विद्यालयों और कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए एक नई व्यापक शैक्षणिक ऋण स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम से छात्रों को लाभ पहुंचा है और लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लगभग 670 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा

67. पिछले वर्ष मैंने उल्लेख किया था कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से एक नई पेंशन स्कीम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा जाएगा ताकि असंगठित क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। आईआरडीए ने व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित अंशदान आधार पर अभिदान करने योग्य बनाने के लिए एक पेंशन निधि गठित करने के लिए एक विनियामक संस्था की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर 30 जून, 2002 तक कार्रवाई की जाएगी।

68. अच्छी और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा सुविधा तक पहुंच अधिकांश ग्रामीण आबादी के लिए अभी भी स्वप्न-मात्र है। बीमा प्रीमियम के रूप में 1 रुपए प्रतिदिन के भुगतान से जरूरतमंद आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा 'जनरक्षा' नामक एक बीमा स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अधीन कोई भी व्यक्ति चयनित और निर्धारित अस्पतालों में प्रति वर्ष 30,000 रुपए तक का अंतरंग उपचार कराने का हकदार होगा। निर्धारित क्लिनिकों, जिसमें सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, निजी न्यास अस्पताल और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी-जा रही अन्य संस्थाएं शामिल होंगी, में प्रतिवर्ष 2000 रुपए तक का बहिरंग उपचार भी शामिल किया जाएगा।

महिला और बच्चे

69. वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था और महिलाओं की अधिकारिता में सहायता करने के लिए कई नीति, विधायी और कार्यक्रम संबंधी पहलें प्रारंभ की गई हैं। मैं महिला और बाल विकास विभाग के लिए आयोजना आवंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 2200 करोड़ रुपए निर्धारित कर रहा हूँ।

70. वैज्ञानिक व्यवसायों में महिलाओं के अधिक संख्या में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का आशय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में कम से कम 100 छात्रवृत्तियां देना है।

71. इसके अतिरिक्त, हमारे देश में बहुत अधिक बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। तदनुसार, प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 अगस्त, 2001 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की घोषणा की। इस मिशन के अधीन आईसीडीएस संरचना के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किशोर बालिकाओं तथा गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

72. चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान को अपनी गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना निजी क्षेत्र की भागीदारी से की जाएगी। मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अगले वर्ष हेतु बजटीय सहायता को पुनः 25 प्रतिशत बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर रहा हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

73. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए आबंटन इस वर्ष 792 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 879 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में सुधार हेतु कई योजनाएं चलायी हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्ति में सुधार हेतु छात्रवृत्तियों तथा छात्रावासों जैसी विभिन्न स्कीमों, खाद्य बैंक की स्थापना, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के तहत अन्य सहायता प्रदान करने वाली स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैंने जनजातीय कल्याण हेतु, आयोजना परियोजना को 21 प्रतिशत तक बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 290 करोड़ रुपए कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

74. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष के दौरान, वर्ष 1998-1999 में स्थापित केन्द्रीय पूल से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गयी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 187 करोड़ रुपए ज्यादा है। विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय आयोजना में से पूर्वोत्तर राज्यों में किए जाने वाले व्यय के प्रावधान को भी चालू वर्ष में 3457 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वर्ष हेतु लगभग 5016 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

75. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आयोजना आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 625 करोड़ रुपए किया जा रहा है जो चालू वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

76. विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की सुविधाएं बढ़ाने हेतु, वर्ष 2000-01 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सुधार संबंधी एक निधि की स्थापना की गयी थी। इस निधि के प्रति व्यक्त उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर मैं इस कार्यक्रम हेतु आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में लगभग 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 75 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूं। इस निधि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग समस्त विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भी किया जाएगा।

77. राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन की स्थापना 20 करोड़ रुपए के संचित कोष से मार्च, 2000 में की गयी थी ताकि उत्कृष्ट पारम्परिक ज्ञान तथा मूल नवाचारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार हो सके। इस प्रयास ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। दूसरे वार्षिक अभियान में, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने सम्पूर्ण देश से 11,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त की, जबकि पहले वर्ष 948 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। इस उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर मैं लघु नवाचारों हेतु लघु उद्यम पूंजी निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं जिसे राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा ताकि उद्यमों में नवाचारों के परिवर्तन को सुगम बनाया जा सके।

मनोरंजन

78. कम्प्यूटर साफ्टवेयर में भारत के वैश्विक नेतृत्व के बाद अब हम मनोरंजन उद्योग के व्यापक रूप से फैले उच्च क्षमता के दूसरे क्षेत्र में भी अग्रणी हो गये हैं। आज, हम विश्व के सबसे बड़े फिल्म निर्माता हैं, हमारे पास तेजी से विस्तार कर रहा प्रसारण क्षेत्र है; संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा का महान खजाना छिपा है; और मनोरंजन उद्योग के संबंध में सभी प्रकार की निविष्टियों का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनने की शानदार सम्भावनाएं हैं। तदनुसार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिए बजटीय सहायता को 22 प्रतिशत तक बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 415 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

79. पिछले वर्ष मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने फिल्म तथा टीवी सॉफ्टवेयर उत्पादन के लिए अब तक 236 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन की उपलब्धता से अच्छी फिल्में बनेंगी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, फिल्मों का निर्यात मोटे तौर पर प्रत्येक वर्ष दुगुना होता रहा है। यही समय है जब हम अपनी राजकोषीय व्यवस्था से मनोरंजन उद्योग में और 'खुशी' लाकर शेष 'गम' को उससे हटाने में समर्थ हुए हैं।

80. 'फिलहाल' आगे की राहों और प्रोत्साहनों को मेरे भाषण के भाग 'ख' में विस्तार से दिया गया है।

राजकोषीय समेकन

81. अपने प्रत्येक वजट भाषण में, मैंने केन्द्र और राज्य सरकारों की खराब राजकोषीय स्थिति पर गहरी चिन्ता बार-बार व्यक्त की है। इस चिन्ता के प्रत्युत्तर में, मैंने दिसम्बर, 2000 में संसद में राजकोषीय दायित्व तथा वजट प्रबन्ध विधेयक प्रस्तुत किया था। वित्त सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों पर हमारा ध्यान गया है और चालू सत्र के अन्तर्गत इस सम्माननीय सदन में विचार हेतु मैं एक विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

82. मैंने अनुमानित राजकोषीय घाटे को वर्ष 2000-2001 सं.अ. में 5.1 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2001-2002 के व.अ. में सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव किया था। औद्योगिक मंदी वर्ष 2000-01 तथा चालू वर्ष दोनों ही में देखी गयी जो सीमा शुल्कों, उत्पाद शुल्कों तथा निगमित आय कर से प्रत्याशित राजस्व संग्रहणों की अपेक्षा काफी कम थी। तथापि, आयोजना भिन्न व्यय पर कठोरता से नियंत्रण रखा गया जिसके परिणामस्वरूप, माननीय महोदय, आपको यह सुनकर हर्ष होगा कि चालू वर्ष में आयोजना भिन्न व्यय वजट में रखी गयी राशि की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए से भी कम है, तथापि, औद्योगिक मंदी तथा अनवरत

सरकारी निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोजना व्यय को न केवल संरक्षित किया जा सका बल्कि यह वास्तव में ब.अ. से अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में भी कमी दिखाई दी है। परिणामस्वरूप, अब चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत होने की आशा है।

83. अपनी राजकोषीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें गैर-उत्पादक व्ययों को नियंत्रित करने तथा अपनी कर-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने हेतु यथासम्भव प्रयास करने चाहिए ताकि राजस्व संग्रहण आगामी वर्षों में उत्साही वृद्धि दिखाए। मैं इस संबंध में अपने भाषण के भाग 'ख' में शीघ्र ही अपनी योजनाएं रेखांकित करूंगा।

84. व्यय का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता घटक सब्सिडियां हैं। यह परमावश्यक है कि उन्हें आगामी 3 से 5 वर्षों की अवधि में घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। तथापि, सुलक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण के पर्याप्त स्तरों तक गरीबों की पहुंच को रोजगार सृजन कार्यक्रमों के साथ सुनिश्चित करना होगा।

व्यय प्रबन्ध

85. आयोजना भिन्न व्यय को नियंत्रित करने में प्राप्त की गयी सफलता ने मुझे इस दिशा में प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशों ने व्यय में हो रही वृद्धि में तुरन्त सन्तुलन स्थापित करने के लिए एक अत्यन्त उपयोगी रूपरेखा प्रस्तुत की है। ई.आर.सी. ने अपना कार्य सितम्बर, 2001 में पूरा कर लिया है और उसने 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया। इन मंत्रालयों/विभागों की कुल स्वीकृत स्टॉफ संख्या 8.65 लाख है। इन मंत्रालयों/विभागों में पहचान किए गए 42,200 अधिशेष जनशक्ति में से लगभग 12,200 पदों को मार्च, 2002 के अन्त तक समाप्त किए जाने की आशा है। शेष रिपोर्टों पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है। कुल सिविलियन स्टॉफ के 1 प्रतिशत तक नवीन भर्ती को सीमित करने संबंधी निर्णय को आगामी 4 वर्षों के लिए निरन्तर कार्यान्वित किया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज की उपलब्धता, जिसे अब अनुमोदित किया जा चुका है, प्रभावित कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा का सुनिश्चय करते हुए स्टॉफ संख्या को घटाने के प्रयास में सहायक होगी।

86. हमने उत्पादन प्रणाली में अकुशलताओं को दूर करके उर्वरक सब्सिडी जिसे उत्पादकों द्वारा और निर्गम मूल्यों में समय-समय पर बढ़ोतरीयों के कारण पहले सरकार की जिम्मेदारी बनाया गया था, को नियंत्रित करने के प्रयत्न किए हैं। व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत मूल्य बढ़ाने चाहिए और अगले पांच वर्षों में नियंत्रण मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। उर्वरकों की कीमतों में पिछले दो वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। मैं यूरिया, डीएपी और एसओपी के निर्गम मूल्य में लगभग 5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि और एसएसपी के लिए सब्सिडी प्रति टन 50 रुपए कम करने का प्रस्ताव करता हूं। जटिल उर्वरकों की कीमतों को भी उचित रूप से संशोधित किया जाएगा। कृषि तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विनिर्दिष्ट बढ़ोतरीयों को अधिसूचित करेंगे।

87. मूल्य और वितरण के नियंत्रण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए 1 मार्च, 2002 से चीनी पर अनिवार्य लेवी की दर को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 से चीनी का खुदरा मूल्य 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम होगा।

88. डाक सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण डाक दरों में मामूली वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

लघु बचतें तथा ब्याज दरें

89. प्रशासित ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु सुझाव देने के लिए मैंने पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। तदनुसार, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:

- प्रशासित ब्याज दरों को अब द्वितीयक बाजार में समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत वार्षिक लाभ तक सीमित रखा जाएगा। तदनुसार, 1 मार्च, 2002 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों को 50 आधार अंकों तक घटाया जा रहा है। भविष्य में ऐसे समायोजन गैर-विवेकाधीन स्वतः आधार पर वार्षिक रूप से किए जाएंगे। लघु बचत जमाशायियों पर ब्याज दरों में कटौती के लाभ को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।
- भारत सरकार राहत बांडों के लिए लागू ब्याज दर में भी 50 आधार बिंदु की तदनु रूप कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन बांडों में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की जा रही है।
- लघु बचतों से प्राप्त सकल निवल आय के 80 प्रतिशत अंतरण की वर्तमान दर को बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को कम ब्याज दर के लाभ सहित लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी उपलब्ध होगी।
- राज्य सरकारें कम ब्याज दर पर उपलब्ध इन अतिरिक्त रासाधनों से अपने पिछले उच्च लागत ऋण की पूर्व-अदायगी कर सकेंगी। राज्य सरकार की लघु बचत ऋण की पूर्व-अदायगी के प्रतिमान को राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
- राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज दर को 50 आधार अंकों द्वारा घटाया जा रहा है।
- केन्द्र द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) की घटाई गई ब्याज दरों के साथ राज्य सरकारों द्वारा समायोजित जी.पी.एफ. की ब्याज दरों से राज्य सरकारों का ब्याज संबंधी बोझ और कम हो जाएगा।
- लघु बचतों संबंधी कर उपायों में संशोधन किए जा रहे हैं जिन्हें मेरे भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है।

90. लघु बचतों संबंधी कर उपायों तथा प्रशासित ब्याज दरों में लंबे समय से वांछित सुधार का कार्यान्वयन अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के विनियमन, जिनसे पिछले 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से जारी रखा गया है, की दिशा में एक और कदम है। भविष्य में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को समान रूप से अपना ब्याज संबंधी बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

पेंशन सुधार

91. सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा पेंशन योजना से सरकार पर बेतहाशा वित्तीय बोझ पड़ता है। सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदानों पर आधारित एक नई पेंशन योजना तैयार करने के लिए मैंने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की घोषणा की थी। विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दल ने एक दोहरी योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें एक तरफ तो कर्मचारियों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य आधार पर अंशदान करने तथा दूसरी ओर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक परिभाषित लाभ देने की वचनबद्धता की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा इस योजना पर विचार किया जा रहा है तथा नयी भर्तियों के लिए 1 जून, 2002 में नई पेंशन योजना घोषित और कार्यान्वित कर दी जाएगी।

निजीकरण

92. विनिवेश और निजीकरण की सरलीकृत प्रणाली के साथ मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियों तथा भारतीय होटल निगम और भारत पर्यटन विकास निगम की कुछ होटल परिसंपत्तियों के नीतिबद्ध बिक्री कार्य को पूरा कर लिया है। शेयरों के छोटे समूहों के विनिवेश से अपना ध्यान हटा कर महत्वपूर्ण निवेशकों को शेयरों के बड़े समूह बेचने की तरफ अपना रुख करने से प्राप्त मूल्य अर्जन अनुपात सुधरे हैं। हमें आशा है कि हम इस वर्ष 6 अन्य कंपनियों तथा एच.सी.आई. और आई.टी.डी.सी. के शेष होटलों में विनिवेश कार्य को पूरा कर लेंगे। वर्तमान वर्ष में 5000 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां होने का अनुमान है जिसमें वी.एस.एन.एल. का 1,887 करोड़ रुपये का विशेष लाभांश शामिल नहीं है। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर अगले वर्ष में फिर से विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति कर रहा हूँ।

रक्षा

93. हमारी सुरक्षा संबंधी तैयारियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन हमारे राष्ट्र की उच्चतम प्राथमिकता है। आगामी वर्ष के लिए मैंने रक्षा व्यय के लिए 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं इस उद्देश्य के लिए और अधिक राशि का प्रावधान करने में नहीं हिचकूंगा। रक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तथा, जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में घोषित किया गया था, रक्षा कर्मियों के लिए आवास निर्माण संबंधी एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय सुधार

94. राज्यों के मामले में राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती भी इतनी ही गंभीर है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थापित की गई राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि के माध्यम से हम राज्यों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। गैर-उत्पादनकारी व्यय को कम करके अपनी राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने साहसिक कदम उठाए हैं। अभी तक 12 राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें प्रोत्साहन निधि से सहायता भी प्रदान की गई है। ब्याज दर में कटौती तथा ऋण विनिमय सुविधा, जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, के साथ-साथ लघु बचत योजनाओं के सुधार से राज्यों को सहायता मिलेगी। संयुक्त रूप से हमारा यह प्रयास होगा कि वर्ष 2005 तक समेकित ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के वहीनीय स्तर तक लाया जा सके।

95. जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि अब हम ए.पी.डी.आर.पी., ए.आई.बी.पी., यू.आर.आई.एफ., आर.आई.डी.एफ. जैसे बहुत से क्षेत्रों के लिए राज्यों को सुधार संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए 12,300 करोड़ रुपए की कुल राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्रों, जो संवर्धन और विकास में बाधा डाल रहे हैं, में नीति संबंधी सुधारों के लिए 2,500 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की गई है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से हम ऐसे कार्यक्रम और नीतियां तैयार कर सकेंगे जिनसे विकास में आड़े आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा और विकास प्रक्रिया की गति तेज होगी और हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बजट अनुमान

वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमान

96. चालू राजकोषीय वर्ष के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 10,787 करोड़ रुपए की गिरावट दर्शाते हैं।

97. 1,63,031 करोड़ रुपए के बजट अनुमान, की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्व 1,42,348 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 20,683 करोड़ रुपए की गिरावट दर्शाते हैं। कमी का मुख्य कारण औद्योगिक मंदी के कारण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम संग्रहण होना है। कर-भिन्न राजस्व 70,224 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 68,714 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 1510 करोड़ रुपए अधिक है। तथापि, 5000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्ति 12,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में काफी कम है।

वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान

98. वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 4,10,309 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से 1,13,500 करोड़ रुपए आयोजनागत तथा 2,96,809 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए हैं।

आयोजना-व्यय

99. केन्द्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 1,13,500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया है जो कि 2001-2002 के बजट अनुमान से 18,400 करोड़ रुपए अधिक है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19.35 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है जो कि पिछले दशक में उच्चतम वृद्धि है। केन्द्रीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता को 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 60,276 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 66,871 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय आयोजना सहायता को भी वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 38,878 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 46,629 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में हुई वृद्धि 11 प्रतिशत से कम है जब कि राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आयोजना-भिन्न व्यय

100. वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 2,65,282 करोड़ रुपए की तुलना में 2002-2003 में आयोजना-भिन्न व्यय 2,96,809 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज अदायगियों (10,133 करोड़ रुपए), सब्सिडी (9,278 करोड़ रुपए), रक्षा (8,000 करोड़ रुपए) तथा राज्य सरकारों को अनुदान (2,196 करोड़ रुपए) के कारण हुई है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2002

No. F. 2(5)-B(D)/2002.—The following is issued for general information :—

Budget 2002-2003

Speech of Shri Yashwant Sinha, Minister of Finance

28th February, 2002

PART A

Sir,

I rise to present the budget for the year 2002-03.

2. The year 2001, the first year of the millennium, was a year of many tragic events. It started with the Gujarat earthquake on January 26, and ended with the terrorist attack on our Parliament on December 13, punctuated by the September 11 incident in the United States and the October 1 outrage in Srinagar. I salute the brave members of our security forces who defended this Parliament and made the supreme sacrifice. On the economic front too it has been a difficult year. World economic growth is estimated to have slowed down to 2.4 per cent in 2001 after seven consecutive years of higher growth. International terror and the global economic slowdown have been the saddest features of the past year.

ECONOMIC CONTEXT

3. Despite the hostile economic and security environment, the economy has performed relatively well this year. After irregular monsoons in the previous two years an agricultural recovery was enabled by a relatively well distributed monsoon this year. Economic growth this year is expected to be about 5.4 per cent: higher growth being constrained by the industrial slowdown. The basic fundamentals of the economy remain strong: inflation has fallen to a record low of 1.1 per cent, foreign exchange reserves have crossed US \$50 billion, and our food stocks have risen to almost 60 million tonnes. The fall in petroleum prices has provided further relief to the economy as a whole.

4. While the country is economically secure there are still many challenges facing us. These have been described in detail in the Economic Survey presented to this House on February 26. My effort is to devise a budget strategy to meet these challenges.

BUDGET STRATEGY

5. In my last budget I had laid out a comprehensive agenda of the second generation economic reforms. I had also deepened tax reforms aimed at providing a modern tax regime. My aim this year is to consolidate and implement these policies at all levels. I propose to take this process further at the State level through a strategy of reform linked public funding.

6. The broad strategy of the budget, therefore, is to:

- Continue the emphasis on agriculture and food economy reforms.
- Enhance public and private investment in infrastructure.
- Strengthen the financial sector and capital markets.
- Deepen structural reforms and regenerate industrial growth.
- Provide social security to the poor.
- Consolidate tax reforms and continue fiscal adjustment at both the Central and State levels.

7. The implementation of the announcements made in the last budget has been closely monitored throughout the year. I started the practice last year to submit to Parliament an Action Taken Report on the previous year's budget. Accordingly, I am presenting a detailed ATR on last year's budget announcements. Some of the highlights are: deregulation of controls on agricultural commodities; progress towards decontrol of sugar; substantial reduction in the span of price control of drugs; decision to amend existing legislation governing revival and/or winding up of companies, along with abolition of SICA; substantial progress in privatization; progress in the implementation of Expenditure Reforms Commission's recommendations and announcement of VRS for surplus government employees.

8. These decisions demonstrate the resolve of this Government to carry forward the process of economic reforms, and to ensure that the benefits reach the common man. This will require improved implementation and governance. We shall put in place measures to effect improvement in these areas with the objective of eliminating poverty and improving the quality of life of our citizens.

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT**Deregulation**

9. Having achieved great success with the Green Revolution and then the White Revolution, the country is now ready for its third revolution of agricultural diversification and food processing. This requires policy changes, a renewed thrust on agricultural research and extension, and a new climate that encourages much greater investment in both the public and private sectors. Removal of the remaining regulatory and procedural rigidities that still exist and improved rural infrastructure is essential for this new revolution. Freedom to the farmer, Kisan Ki Azaadi is the overarching goal of our policy.

10. Even though agriculture is a State subject, there are a number of Central Government policies that influence this sector. The Government has reviewed the operation of the Essential Commodities Act, 1955. Restrictive orders inhibiting storage, selling and movement of food and agricultural products are being removed. We can now look forward to a countrywide integrated market for agricultural products. To continue this initiative, I am proposing further decontrol and deregulation of agriculture along the following lines:

- Amendment of the Milk and Milk Products Control Order (MMPO) to remove restrictions on new milk processing capacity, while continuing to regulate health and safety conditions.
- Removal of small scale industry reservations related to various agricultural equipment items.
- Decanalization of the export of agricultural commodities and phasing out of remaining export controls.
- Expansion of futures and forward trading to cover all agricultural commodities.

11. A multiplicity of regulations for food standards under the Prevention of Food Adulteration Act, the Food Products Order, the Meat Products Order, the Bureau of Industrial Standards and the MMPO, affect the food and food processing sectors. They need to be modernised and converged. The Prime Minister has decided to set up a Group of Ministers (GOM) to propose legislative and other changes for preparing a modern integrated food law and related regulations.

12. This process of providing freedom to the farmers now needs to be carried forward by State Governments. Amendment of the Agricultural Produce Marketing Acts to enable farmers to sell directly to potential processors would help them to receive better prices and to access potential new markets. In addition, the remaining State control orders which are acting as barriers to inter-State trade need to be lifted. I am proposing that additional allocations in respect of centrally sponsored schemes would be linked to decontrol and deregulation of the agricultural sector by the States.

13. In 2000-01, I had announced a Credit Linked Subsidy Scheme for construction of cold storages. I am happy to report that sanction has already been given for the creation of 21 lakh tonnes capacity in cold storages, much higher than the target of 12 lakh tonnes. The rural godown scheme announced last year has also become operational. With the removal of various control orders much greater investment would be forthcoming under both these schemes. Accordingly, I propose to allocate Rs 70 crore to each of these subsidy linked credit schemes in 2002-03.

Agricultural Credit

14. As Finance Minister I feel particularly responsible for the flow of adequate credit to the agriculture sector. I am glad to report that the total credit flow to the agriculture sector through institutional channels is expected to reach the targeted level of Rs 64,000 crore this year. It is expected to increase to

Rs 75,000 crore in 2002-2003. I propose the following steps to further improve the delivery of agricultural credit:

- The funds for RIDF VIII will be enhanced from Rs 5000 crore to Rs 5500 crore next year, while the rate of interest will be reduced from 10.5 per cent to 8.5 per cent. Henceforth it will be fixed at the prevailing bank rate plus 2 per cent. Assistance to the States from RIDF will be linked to reforms in the agriculture and rural sectors.
- Kisan Credit Cards introduced in 1998-99, have been a resounding success and have helped our farmers considerably in their access to agricultural credit. An additional 63 lakh KCCs have been issued upto December 31, 2001 taking the total to 2.07 crore. The personal insurance package linked to KCCs has also been operationalised.
- Similarly, the scheme of micro credit through Self Help Groups is progressing well. The target of one lakh additional self-help groups during the current year is expected to be achieved taking the total so far to more than 3.5 lakh covering more than 70 lakh families, making it the largest micro credit programme in the world. I am raising the target to 1.25 lakh for 2002-03.
- A one-time settlement scheme for small loan accounts with outstanding principal balance upto Rs 25,000 as on March 31, 1998 is already in operation. A special OTS scheme for small and marginal farmers will be announced by RBI to cover loans upto Rs 50,000.

Crop Insurance

15. The National Agriculture Insurance Scheme is already in operation. To subserve the needs of farmers better and to move towards a sustainable actuarial regime I propose to set up a new Corporation for Agriculture Insurance to be promoted by the existing public sector general insurance companies.

Irrigation

16. I propose to increase the allocation for the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) from Rs 2000 crore this year to Rs 2800 crore in 2002-03. This will assist the States to accelerate the completion of unfinished medium and major irrigation projects, and also to undertake reforms by revising user charges and setting up of water users associations.

Agriculture Extension and Research

17. The accelerated diversification and modernization of agriculture will require a new approach to research and extension services. I therefore propose to enhance the allocation for 2002-03 for agriculture research to Rs 775 crore from Rs 684 crore in the current year. A full review of the governance of agricultural research is also proposed so that the system can serve the new needs creatively.

18. Linkages between research and extension will be strengthened to improve quality and effectiveness of research and extension systems. The extension system will be revitalised and broad-based through Krishi Vigyan

Kendras (KVKs), NGOs, farmers organisations, cooperatives, the corporate sector and agri-business clinics. KVKs will be designated as nodal agencies for quality certification including organic products, bio-fertilizers, and bio-pesticides. The supply of inputs, agro-processing and trade through such cooperatives/ companies will be encouraged through the availability of credit with the help of NABARD. The Companies (Second Amendment) Bill 2001, already introduced in Parliament will enable the conversion of existing producer cooperative businesses into companies.

Agricultural Exports

19. Promotion of agricultural exports is important for creating conditions for providing remunerative prices to farm produce. For this purpose Agri Export zones are being promoted in different States and 15 such zones have been approved so far. APEDA will catalyse development of infrastructure and flow of credit to the units in these Agri Export zones.

RURAL DEVELOPMENT

Rural Roads

20. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) initiated to provide connectivity through all weather roads to all our villages is making considerable headway. A further allocation of Rs 2,500 crore for the year 2002-03 is being made over and above Rs 5,000 crore provided so far. Depending on the accelerated implementation of these works I intend to find additional resources including those from multilateral sources in the course of the year.

Rural Electrification

21. During my last budget speech I had announced a package of initiatives for electrification of 80,000 villages that have no access to electricity. Considering the fact that SEBs find it difficult to service debt, the Government proposes to introduce a new interest subsidy scheme called the Accelerated Rural Electrification Programme. An outlay of Rs 164 crore has been provided for this scheme in 2002-03.

Rural Employment

22. The Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) announced by the Prime Minister in his Independence Day speech of 2001 was launched on September 25, 2001 by merging the ongoing Employment Assurance Scheme (EAS) and the Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY). Since the launch of the scheme, release of 30.6 lakh tonnes of food grains to States has already been authorised, out of the 50 lakh tonnes allocated. This scheme will be continued next year. I urge upon all the States to come forward to take full advantage of the free foodgrains being offered under this scheme.

23. Lok Nayak Shri Jai Prakash Narayan always had a special concern for the disadvantaged. In his birth centenary year I propose to launch the Jai Prakash Rozgar Guarantee Yojana (JPRGY) to provide employment guarantee to the unemployed in the most distressed districts of the country. A Task Force

headed by my colleague, the Minister of Rural Development, will be set up to design and implement a massive programme for employment generation in these districts. KVIC, DC (SSI), and other agencies will be fully involved in the implementation of this scheme.

24. The promotion of rural industrialisation would be helped greatly through capacity building and technology upgradation in Khadi and Village Industries. To help in this effort I propose to upgrade the Wardha Institute started by Mahatma Gandhi in 1935 as a national institute to be called Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation.

25. The diversification of agriculture will not succeed without appropriate infrastructure for marketing. For this purpose, rural local bodies, cooperatives and NGOs will be assisted to set up rural produce marketing centres and sub-centres at the district and block levels and to upgrade village haats under a special scheme of the Swaran Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SJGSY).

26. Some parts of our country have been particularly afflicted with natural calamities. Additional allocation of Rs 480 crore was provided under the Indira Awas Yojana for the affected States. Houses constructed by the poor under the Indira Awas Yojana (IAY) in such disaster prone areas will henceforth be provided insurance cover through a Master Policy.

Management of the Food Economy

27. I had drawn attention last year to the severe policy and fiscal difficulties arising from the growing mismatch between the unprecedented level of procurement of wheat and rice by FCI and the much lower PDS and buffer stock needs in the last few years. The current situation of open-ended procurement by FCI at a high price and disposal at a heavily subsidised price is not sustainable. The concept of decentralised procurement has not yet found favour with the States. The report of the High Level Committee on Long Term Grain Policy is expected to be submitted shortly. We shall formulate a more durable approach for better management of our food economy after considering this report.

28. A number of steps have been taken by the Government to reduce the high food grain stocks that are posing serious problems of storage and disposal. These measures include: increased allocations for BPL families; launching of a major food for work programme under the SGRY; allocation of 30 lakh tonnes of free foodgrains to States for relief works in areas affected by natural calamities; open market sales of 30 lakh tonnes this year compared to 5.5 lakh tonnes in 2000-2001; and enhanced incentives for export of food grains.

INFRASTRUCTURE

29. Provision of efficient and world class infrastructure is critical for our growth aspirations. A key issue that bears repetition is the imposition of appropriate user charges necessary to provide adequate returns on investment. Some success has been achieved in areas such as telecom, roads and ports where appropriate user charges exist. With the tariff rationalization and other bold measures introduced by my colleague, the Minister of Railways, we can

expect the Railways to serve well the key transportation needs of the country in the years to come. Other areas such as power, urban infrastructure, other transportation and the like continue to experience great difficulty because of the lack of appropriate user charges.

Power

30. Restoration of financial viability in the power sector remains crucial. The average rate of return for all SEBs is about minus 40 per cent and their combined losses continue to increase. Hence, this is one of the foremost challenges not only in the power sector but also for the fiscal health of the state governments and the overall performance of the economy.

31. In recognition of these severe problems the Prime Minister held a meeting with State Chief Ministers on March 3, 2001. While broadly agreeing with the desirability of power sector reforms to achieve commercial viability of State Electricity Boards, the conference placed special emphasis on distribution reforms and elimination of theft of electricity. Subsequently, the high level empowered group of Chief Ministers and Union Ministers has agreed to a one time settlement scheme in regard to SEB overdues to the Central Public Sector Utilities through securitisation and issue of tax free bonds by the respective State Governments, subject to the achievement of specified performance milestones and full payment of current dues in the future. I would urge upon the States to come forward and implement the scheme speedily.

32. The Ministry of Power has already signed Memoranda of Understanding (MOUs) with 20 States and is expected to complete the exercise with the remaining States soon. To redouble our effort in this direction APDP is being redesigned as the Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP), with an enhanced plan allocation of Rs 3,500 crore for 2002-03, up from Rs 1,500 crore this year. Access of the States to the fund will be on the basis of agreed reform programmes, the centre piece of which would be the narrowing and ultimate elimination of the gap between unit cost of supply and revenue realisation within a specified time frame. Accordingly, the focus of reform has shifted from generation to transmission and distribution.

33. A high level monitoring group will oversee the progress of this programme. Allocation for this programme will be augmented by loans on concessional terms from the Power Finance Corporation (PFC).

Roads

34. I am glad to inform the House that the Prime Minister's National Highway Development Programme (NHDP) launched three years ago is progressing well. It now promises to achieve a totally new scenario in the road sector. The Golden Quadrilateral will be completed substantially by December 2003, a year ahead of schedule. The North-South East-West corridors have a length of 7300 kms., of which 716 kms. have already been four-laned. With the assistance of multilateral funding, other borrowings by the National Highway Authority of India (NHAI) with government guarantee, and other innovative financing schemes, the funding for this phase will be fully tied up in 2002-03.

Ports

35. The present Port Trust structure does not allow Indian major ports to have the flexibility needed for efficient management and for raising institutional funding. It is therefore proposed to corporatise major ports in a phased manner. Private sector investments have been facilitated and 17 projects worth more than Rs 4,500 crore have already been approved and another 8 projects worth more than Rs 3,200 crore are under consideration. With corporatisation of the existing ports and new private sector ports coming up, the regulatory structure will be strengthened.

Civil Aviation

36. The Government has already announced its decision to upgrade the international airports at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata to the standards of world class airports by inducting private sector management and investment through long term leasing systems. Modalities for inviting offers have been finalised and the leasing process will be completed in 2002-03.

37. Private sector participation in greenfield airports will be encouraged through a package of concessions:

- ♦ Availability of land and related infrastructure from the State Governments.
- ♦ Exemption from levy of Inland Air Travel Tax (IATT) and Foreign Travel Tax (FTT) on departing passengers for projects located in States that charge sales tax on Aviation Turbine Fuel (ATF) at Central Sales Tax (CST) rate.
- ♦ Charging of Advance Development Fee (ADF) by way of additional Passenger Service Fee (PSF) at the existing airports for help in financing of the greenfield airport.
- ♦ Levy of User Development Fee (UDF) at the new airport.
- ♦ Financial assistance/equity participation by Airports Authority of India.

The proposed new airports in Bangalore and Hyderabad will benefit from these concessions.

Urban Development

38. The 2001 census shows that the urban population in India is now about 285 million, greater than the total population of the United States. The number of cities with more than one million population has increased from 23 in 1991 to 35 in 2001. We are aware of the sad plight of most of our towns and cities. This needs to be changed if they have to act as engines of growth, and if they are to provide a healthy environment for our citizens. Hence, we can no longer afford to delay reforms in this sector.

39. I propose to set up an Urban Reform Incentive Fund (URIF) with an initial allocation of Rs 500 crore to provide reform linked assistance to States. The Fund will seek to incentivise reforms in the following areas:

- ♦ Reform of Rent Control Laws and repeal of Urban Land Ceiling Acts.
- ♦ Rationalisation of high stamp duty regimes.
- ♦ Revision of bye-laws to streamline the approvals process for construction of buildings, development of sites, etc.
- ♦ Revision of municipal laws in line with model legislation prepared by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation.
- ♦ Simplification of legal and procedural frameworks for conversion of agricultural land for non-agriculture purposes.
- ♦ Levy of realistic user charges and resource mobilization by urban local bodies.
- ♦ Initiation of public private partnership in the provision of civic services.

40. A City Challenge Fund (CCF) will also be set up as an incentive based facility that will support cities to fund transitional costs of moving towards sustainable and creditworthy institutional systems of municipal management and service delivery. It will assist in the partial financing of the cost of developing an economic reform programme and financially viable projects to be undertaken by urban local bodies. It is also proposed to set up a Pooled Finance Development Scheme to provide credit enhancement to assist local bodies to access market borrowing on a creditworthy basis. To provide a further incentive for urban local bodies to become credit worthy and to invest in urban infrastructure I am providing for the issue of municipal tax free bonds upto Rs 500 crore in 2002-03, up from Rs 200 crore this year.

Tourism

41. Tourism constitutes a priority area in view of its beneficial impact on growth of employment, generation of foreign exchange, and the promotion of greater national integration through domestic tourism. It is therefore proposed to implement a comprehensive tourism development package:

- ♦ 6 tourism circuits would be identified for development to international standards during 2002-03.
- ♦ Special Purpose Vehicles (SPVs) will be permitted to raise resources from both public and private sectors for infrastructure development in these circuits.
- ♦ One special area, the World Heritage Site of Hampi, will be developed as an international destination for tourism based on an integrated master plan.

42. The Plan Outlay for tourism has accordingly been increased by 50 per cent to Rs 225 crore for 2002-03. I will have more to say on the fiscal measures relating to tourism in part B of my speech.

Infrastructure Finance

43. Members are aware of the continuing effort that we have made to attract private sector investment in the infrastructure sector to supplement public investment. The flow of investment has however been slow except in the telecom

sector. I therefore propose to take the following measures to facilitate faster private investment in infrastructure facilities:

- ♦ An Infrastructure Equity Fund of Rs 1000 crore will be set up to help in providing equity investment for infrastructure projects. Contributions to the Fund to be managed by the Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC), would initially be made by public sector insurance companies, financial institutions and some banks.
- ♦ An institutional mechanism is being set up to coordinate the debt financing by financial institutions and banks of infrastructure projects larger than Rs 250 crore. IDFC will act as the coordinating institution with primary responsibility for different sectors being shared with the IDBI and ICICI.
- ♦ Public private partnerships will be encouraged for the provision of infrastructure facilities, the modalities for which are being worked out by a Task Force.

Public Investment

44. Public Investment in key infrastructure sectors is also being sharply stepped up. Plan outlay inclusive of internal and extra budgetary resources in power, roads and national highways and railways is being increased by 22 per cent, 39 per cent and 23 per cent respectively, to a total of Rs 37919 crore.

FINANCIAL SECTOR AND CAPITAL MARKET

Debt Market

45. Substantial progress has been made on the proposals made last year for the development of a transparent and active debt market in general and the government securities market in particular. Primary issuance of government securities is now being facilitated by an electronic Negotiated Dealing System (NDS) and efficiency of trading in government securities is being enhanced by the new Clearing Corporation of India Limited (CCIL). To help investors plan their investments better and to add transparency and stability in the market RBI will announce an issuance calendar for dated government securities. Having now received the concurrence of all state legislatures I also propose to introduce a new Government Securities Bill to replace the old Public Debt Act 1949 within this Parliament Session.

Capital Market

46. In view of the various disturbances that have occurred in the capital market it is important to boost investor confidence and to strengthen market integrity. The following measures are being taken.

- ♦ The process of demutualisation and corporatisation of stock exchanges is expected to be completed during the course of the year, to implement the decision to separate ownership, management and operation of stock exchanges. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has already prohibited the induction of broker members in management positions in stock exchanges.

- ♦ Legislative changes will be proposed, during the Budget Session, in the SEBI Act, 1992 for investor protection, and to enhance the effectiveness of SEBI as the capital market regulator.
- ♦ Following certain developments overseas, and within the country, regarding accounting standards and effectiveness of auditors, it is proposed to strengthen regulation in this area.
- ♦ Foreign institutional investors (FIIs) can invest in a company under the portfolio investment route beyond 24 per cent of the paid up capital of the company with the approval of the general body of the shareholders by a special resolution. I propose that now FII portfolio investments will not be subject to the sectoral limits for foreign direct investment except in specified sectors. Guidelines in this regard will be issued separately.

47. Further measures have been taken to develop and deepen the capital market:

- ♦ Badla trading has been banned and practically all trading of stocks is now in the rolling settlement mode.
- ♦ Exchange traded derivatives have become wider with a greater choice of instruments and deeper in terms of liquidity.
- ♦ Individual stock options and index stock options were introduced in July 2001, and individual stock futures in November 2001.
- ♦ Foreign Institutional Investors (FIIs) are now permitted to trade in all stock traded derivative products within specified trading limits.
- ♦ An Investor Education and Protection Fund has been set up from October 1, 2001 to credit certain unclaimed and unpaid amounts.

48. A package of measures for reforming the US-64 scheme and the Unit Trust of India (UTI) has been announced which seeks to balance investors' interest while ensuring systemic safety. The long overdue reform for making US-64 NAV based has been implemented. Further legislative changes in the UTI Act to put in place other needed reform measures will be proposed during the year.

Banking Sector

49. Reforms in the banking sector will be continued to enhance the efficiency and competitiveness of the sector. The following measures have either been taken or are being taken:

- ♦ Public sector banks recovered Rs 12,860 crore in 2000-01 as compared with Rs 9,883 crore in the previous year and net NPAs as percentage of net advances came down to 6.7 per cent as on March 31, 2001 as compared to 7.4 per cent in the previous year.
- ♦ 29 Debt Recovery Tribunals and 5 appellate tribunals have been set up. As on September 30, 2001 the DRTs had disposed of 18703 cases involving Rs 14,026 crore. Recovery made was Rs 3,527 crore.

- ◆ To help banks and financial institutions to make provisions for NPAs as required by the RBI, additional fiscal relief is being offered, details of which will be given in part B of my speech. This will enable banks to review their lending rates.
- ◆ A new Bill on Banking Sector Reforms is proposed to be introduced in Parliament to strengthen creditor rights through foreclosure and enforcement of securities by banks and financial institutions. This Bill will also enable securitisation for money locked up in long term loans.
- ◆ A pilot Asset Reconstruction Company will be set up by June 30, 2002 with the participation of public and private sector banks, financial institutions and multilateral agencies. This company will initiate measures for taking over non performing assets in the banking sector and also develop a market for securitised loans.
- ◆ The Deposit Insurance Credit and Guarantee Corporation (DICGC) will be converted into the Bank Deposits Insurance Corporation (BDIC) to make it an effective instrument for dealing with depositors' risks and for dealing with distressed banks. Appropriate legislative changes will be proposed for this purpose.
- ◆ Reforms in the financial sector have posed new challenges for the development finance institutions (DFIs) like IDBI. It is proposed to make legislative changes to corporatise IDBI within the coming year to provide it appropriate flexibility. Meanwhile IDBI's tier one capital is being strengthened by conversion of existing IBRD and NIC (LTO) loans in to appropriate long term instruments.
- ◆ Consequent to certain amendments made in the year 2000 in the Companies Act, 1956, directors incur disqualification for election in the case of certain defaults by the company. It is proposed to exempt nominee directors of public financial institutions and banks from this provision.
- ◆ Three public sector banks had been classified as weak banks on the basis of criteria suggested by the Committee on Banking Sector Reforms in 1997-98. Two of these banks namely UCO Bank and United Bank of India have turned around and have started making profits. Though the Indian Bank has also shown improvement, its capital adequacy ratio remains deficient. A provision of Rs 1300 crore is proposed for re-capitalisation support to this bank, on the basis of a commitment to Government for implementing monitorable reform measures.

50. In the banking sector foreign banks are permitted to operate in India as fully owned branches with specific permission of the Reserve Bank of India. As recommended by the Committee on Banking Sector Reforms, it has now been decided to give an option to foreign banks to either operate as branches of their parent banks or to set up subsidiaries. A foreign bank will have to choose only one of the two options. Such subsidiaries will have to adhere to all

banking regulations, including priority sector lending norms, applicable to other domestic banks. Necessary amendments will be proposed in the Banking Regulation Act 1949 to relax the maximum ceiling of voting rights of 10 per cent for such subsidiaries.

51. The cooperative credit structure, which is critical for the agriculture sector, has low capital adequacy and high NPAs, is in urgent need of reform. I had appointed a Committee under the then Deputy Governor of RBI to examine its functioning closely. The recommendations of this Committee have been discussed widely by Chief Ministers and in a joint committee of Cooperation Ministers under the chairmanship of my colleague, Shri Vikhe Patil. Reform measures such as the adoption of a Model Cooperative Act, removal of dual control between State Governments and the RBI, regular conduct of elections, larger stake of the members, professionalisation of management etc. have been recommended. The recapitalisation formula suggested is 60:40 between the Central and State Governments along with increases in share capital of members. States will have to consider and accept their funding share and implement the suggested measures for reform. Even though this is a state subject the Government of India will go out of its way to help in the process. To start the process I am making a token provision of Rs 100 crore and depending on the pace of reform, provision of additional funds will be considered.

Housing Finance

52. The initiatives taken in the housing finance area in the last four years have shown positive results. Total disbursement from housing finance institutions in 2000-01 was Rs 26,300 crore, a growth of about 28 per cent in the year. This amount financed the construction of about 28 lakh houses, much higher than the annual target of 20 lakh houses. In the current year the growth rate is expected to be around 35 per cent. To further strengthen housing finance the following measures are being taken:

- ♦ Consequent to the amendment to the National Housing Bank Act, NHB has commenced securitisation of housing loans and is operationalising foreclosure of mortgages.
- ♦ The NHB will launch a Mortgage Credit Guarantee Scheme, which would be provided to all housing loans thereby fully protecting lenders against default. This will make housing credit more affordable thereby also increasing access to housing credit in rural areas.
- ♦ The target under the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme is proposed to be increased to 2.25 lakh for 2002-03, up from 1.7 lakh in the current year. About 1 lakh units have already been financed up to December 2001.
- ♦ The allocation of the Indira Awas Yojana is being increased by 13 per cent to Rs 1725 crore for 2002-03.

I will have more to say on housing in Part B of my speech.

Capital Account Liberalisation

53. Capital account convertibility has been on our agenda for quite some time. In view of the many disturbances that have taken place in international capital markets in recent years I propose to continue with our policy of liberalisation with caution. Accordingly, I propose to take the following steps to further liberalise the capital account:

- ◆ There will be full convertibility of deposit schemes for Non Resident Indians. The existing Foreign Currency Non-Resident (FCNR(B)) scheme and the Non-Resident External rupee (NRE) scheme will continue to be repatriable.
- ◆ The schemes which do not offer full convertibility to NRIs will be discontinued from April 1, 2002. The existing balances in the non-resident (non-repatriable) rupee accounts will be allowed to be credited on maturity to the convertible NRE account.
- ◆ NRIs will be free to repatriate in foreign currency their current earnings in India such as rent, dividend, pension, interest and the like based on appropriate certification.
- ◆ Indian companies wishing to invest abroad may now invest up to US \$ 100 million on an annual basis through the automatic route, up from the existing limit of US \$ 50 million.
- ◆ Indian companies making overseas investment in joint ventures abroad by market purchases may now do so without prior approval up to 50 per cent of their net worth, up from the current limit of 25 per cent.
- ◆ Corporates with proven track record will be allowed to contribute funds from their foreign exchange earnings for setting up chairs in educational institutions abroad and for other welfare measures, likely to benefit the community abroad, on a case by case basis by the RBI.
- ◆ Indian mutual funds will now be allowed to invest in rated securities in countries with fully convertible currencies, within the existing limits. Earlier such investment was only permitted in ADR/GDRs issued by Indian companies in overseas markets.
- ◆ Pre-payment of ECBs is permissible to the extent of balances available in EEFC accounts, which are currently restricted to 50 per cent of export proceeds. To enable ECB holders to benefit from lower interest rates, utilisation of higher amounts from export proceeds will be considered by RBI.
- ◆ With a view to further liberalising the capital account transactions it is proposed to put the Foreign Currency Convertible Bond (FCCB) scheme under the automatic route upto US \$ 50 million.

The Reserve Bank of India will be issuing guidelines for each of these measures separately.

54. While liberalising the capital account is necessary we have to exercise careful vigilance in curbing illegal capital flows. Recent evidence indicates transfer of large sums of money through various channels in support of terrorist activities in the country. The Government, therefore, proposes to bring suitable legislation during the current session of Parliament to empower the enforcement agencies to arrest and prosecute the hawala operators/money launderers suspected to be engaged in financial transactions linked with terrorist activities.

STRUCTURAL REFORMS

Administered Price Mechanism (APM) for Petroleum

55. As decided by the Government in November 1997 and reiterated by me last year, I am glad to announce the dismantling of the Administered Price Mechanism (APM) in the petroleum sector from April 1, 2002. As a result, the following measures are being taken:

- ◆ The pricing of petroleum products will become market determined.
- ◆ The Oil Pool Account will be dismantled on April 1, 2002 and the outstanding balances will be liquidated by issue of oil bonds to the concerned oil companies.
- ◆ Private companies will be permitted in distribution subject to specified guidelines.
- ◆ A Petroleum Regulatory Board will be set up to oversee the sector.
- ◆ Subsidies to refineries in the North-East will continue on a rationalised basis.
- ◆ Freight subsidies will continue to be provided for LPG and kerosene to far-flung areas.
- ◆ As a result of the dismantling of APM, the price of diesel will come down by around 50 paise per litre and of petrol by around Re 1 per litre. These changes in prices will come into effect from March 1, 2002, initially as part of the Oil Pool Account.
- ◆ The 1997 Government decision on the dismantling of APM mandated the subsidy on LPG and kerosene oil to be reduced to 15 and 33 per cent respectively by April 1, 2002. Accordingly, the price of LPG is being raised by about Rs 40 per cylinder and of kerosene oil for PDS by about Rs 1.50 per litre from March 1, 2002. These subsidies will be borne by the consolidated fund from April 1, 2002.
- ◆ The subsidies on LPG and kerosene will be on a specified flat rate basis from April 1, 2002. The retail prices will then vary as the price of crude oil changes in international markets.
- ◆ These subsidies will be phased out in the next 3 to 5 years.
- ◆ The post APM excise and customs duty changes will be spelt out in Part B of the speech. Since the subsidy burden will be borne by the Union budget from next year, the taxation measures have been designed to raise the required resources.

56. I believe that this package of measures for dismantling of APM meets the requirements of consumers and producers. It will also create a more competitive environment in this vital sector.

57. Further details of the dismantling of APM will be announced separately by my colleague, the Minister for Petroleum and Natural Gas.

Industrial Restructuring

58. To deal with forces of competition, industrial and other companies require restructuring on a continuous basis. For this purpose it is essential to promote out of court mechanisms for timely and transparent corporate debt restructuring of viable entities, in addition to the use of legal avenues of financial restructuring. A mechanism for Corporate Debt Restructuring (CDR) has been set up under the guidelines issued by the Reserve Bank of India. I have decided to set up a small group consisting of bankers and others, under the chairmanship of Deputy Governor, Reserve Bank of India to suggest measures to make its operation more efficient.

59. In Part B of my speech I will provide for specific fiscal measures for strengthening certain key industries including steel and textiles and other measures for improving the competitiveness of the manufacturing sector.

Small Scale Industries

60. As Hon'ble Members are aware, small scale industries are now subject to increasing competition with the completion of trade liberalisation. A new approach to the promotion of small scale industries therefore, has already been adopted.

61. Adequate credit flow is essential for the small scale sector. The net bank credit outstanding to small scale industries increased from Rs 45,789 crore on March 31, 2000 to Rs 48,445 crore on March 31, 2001. In order to further increase the flow of credit:

- ◆ The limit for composite loans has been increased from Rs 2 lakh to Rs 5 lakh.
- ◆ 391 specialised branches of public sector banks have been opened for small scale industries as of September 30, 2001.
- ◆ The exemption limit for collateral security has been increased from Rs 25,000 to Rs 5 lakh. The project cost limit under the National Equity Fund has been increased from Rs 25 lakh to Rs 50 lakh.
- ◆ The extension of credit to SSI has already been facilitated through the Credit Guarantee Scheme and the Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation.
- ◆ Encouraged by the Kisan Credit Card Scheme, public sector banks have now decided to introduce a scheme called Laghu Udyami Credit Card (LUCC) Scheme for providing simplified and borrower friendly credit facilities to small businessmen, retail traders, artisans and, small entrepreneurs, professionals and other self employed persons, including those in the tiny sector.

62. Members will recall that last year I had announced the dereservation of 14 items in the footwear, leather goods and toy sectors. The Government has been engaged in discussions with stake holders in respect of certain other items in the reserved list. Over 50 items of knitwear, certain agricultural implements, auto components, some chemicals and drugs, and others will now be dereserved. My colleague, the Minister of Small Scale Industries will announce the details of these items separately.

Exports

63. The Government is committed to provide all assistance to accelerate export growth. A key new initiative is the establishment of Special Economic Zones (SEZs). I will announce a comprehensive package for SEZs in Part B of my speech.

64. To provide incentives to State Governments for export promotion through the creation of new export promotion industrial parks and associated facilities, I propose to increase the outlay for the scheme from Rs 97 crore this year to Rs 330 crore for 2002-2003. Overall outlay for the Department of Commerce for the year 2002-03 has been increased by 55 per cent to Rs 775 crore.

HUMAN DEVELOPMENT

Education

65. The 93rd amendment of the Constitution has made free and compulsory education for all children in the 6 to 14 age group a fundamental right. Necessary infrastructure for making this possible will be created. Accordingly, the plan allocation to the Department of Elementary Education and Literacy is being enhanced from Rs 4,000 crore this year to Rs 4,900 crore for 2002-03.

66. Last year I had announced a new comprehensive educational loan scheme to cover all courses in schools and colleges in India and abroad. The scheme has served the students well and loans amounting to about Rs 670 crore have already been given to almost 50,000 students.

Social Security

67. Last year I had mentioned that the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) would be asked to provide a road map for a new pension scheme so that the unorganised sector is provided adequate social security coverage. IRDA has recommended a regulatory framework for setting up pension funds to enable individuals to subscribe on a defined contribution basis to obtain the benefit of pensions on their retirement. Action on these recommendations will be taken by June 30, 2002.

68. Access to good and responsive health care is still a distant dream for the majority of the rural population. An insurance scheme called "Janraksha" is being designed by the public sector insurance companies to provide protection

to the needy population. With a payment of Re. 1 per day as insurance premium, a person will be entitled to indoor treatment up to Rs 30,000 per year at selected and designated hospitals. Out patient treatment upto Rs 2,000 per year will also be covered at designated clinics which would include civil hospitals, medical colleges, private trust hospitals and other NGO run institutions.

Women and Children

69. The year 2001 was celebrated as the Women's Empowerment Year and several policy, legislative and programme initiatives have been launched to help in the empowerment of women. I am increasing the plan allocation for the Department of Women and Child Development by 33 per cent to Rs 2200 crore.

70. In order to encourage the entry of large numbers of women into scientific professions, the government intends to institute at least 100 scholarships a year to be provided by the Department of Science and Technology to women scientists and technologists.

71. Far too many children in our country continue to suffer from malnutrition. Accordingly, the Prime Minister announced a National Nutrition Mission in his Independence Day speech on August 15, 2001. Under this Mission food grains at subsidised rates would be made available to adolescent girls and expectant and nursing mothers belonging to below poverty line families through the ICDS structure.

Indian System of Medicine

72. The National Institute of Siddha at Chennai is being provided Rs 4 crore for commencing its activities. A National Ayurvedic Hospital will be set up at Delhi with private sector participation. I am further increasing the budgetary support for ISM next year by 25 per cent to Rs 150 crore.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

73. The allocation for the welfare and upliftment of Scheduled Castes in the Ministry of Social Justice and Empowerment has been increased from Rs 792 crore this year to Rs 879 crore in the coming year. The Ministry of Tribal Welfare has launched a number of schemes to improve the social and economic life of scheduled tribes. In order to meet the requirements of various schemes such as scholarships and hostels for improved access to quality education, the establishment of Grain Banks, and other support schemes under the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC), I have increased the plan outlay for tribal welfare by 21 per cent to Rs 290 crore for 2002-03.

Development of the North Eastern Region

74. I am glad to inform the House that during the current year an additional sum of Rs 500 crore was provided to the North Eastern States from the Central Pool set up in 1998-1999. This is Rs 187 crore more than last year.

The provision for expenditure in North Eastern States out of the Central Plan of various Ministries has also been increased from Rs 3,457 in the current year to about Rs 5,016 crore next year.

Science and Technology

75. The plan allocation for the Department of Science and Technology is being raised to Rs 625 crore in 2002-03, an increase of more than 52 per cent over the current year.

76. A fund for the improvement of Science & Technology (FIST) was established in 2000-01 for augmenting laboratory facilities in Universities. Encouraged by the enthusiastic response to this fund I propose to increase the allocation for this programme to Rs 75 crore in 2002-03, an increase of almost 115 per cent. Resources from this fund can now also be used to augment library facilities in the Universities.

77. The National Innovation Foundation was set up in March 2000 with a corpus of Rs 20 crore, in order to build a national register of outstanding traditional knowledge and grass root innovations. This initiative has shown good results. In the second annual campaign NIF has received more than 11,000 entries from all over the country, up from 948 entries in the first year. Encouraged by this enthusiastic response I propose to set up a micro venture capital fund for small innovations to be initiated by the Small Industries and Development Bank of India (SIDBI), in cooperation with the National Innovation Foundation, to facilitate the transition of innovations into enterprises.

Entertainment

78. India's global leadership in computer software must now be complemented by another area of our core competence, the vast terrain of the entertainment industry. Today, we are the world's largest producer of films; we have a rapidly expanding broadcasting sector; a huge reservoir of talent in music; and a promising potential to become the international hub for all types of inputs for the entertainment industry. Accordingly, the budgetary support for the Ministry of Information and Broadcasting is being increased by 22 per cent to Rs 415 crore for 2002-03.

79. With the industry status to the entertainment sector brought into effect last year, banks and financial institutions have sanctioned more than Rs 236 crore, so far, for film and TV software production. Good money will certainly lead to good films. Film exports have been roughly doubling every year, during the last 3 years. It is time we brought about a fiscal regime to usher in more "Khushi" and take away the remaining "Gham" from the entertainment industry.

80. "Filhal" I shall have more to say on this in Part 'B' of my speech.

FISCAL CONSOLIDATION

81. In every budget speech I have, at the risk of irritating repetition, expressed my deep concern at the poor fiscal situation of the Central and State

Governments. Reflecting this concern I had introduced in Parliament the Fiscal Responsibility and Budget Management Bill in December 2000. The recommendations of the Parliamentary Standing Committee of Finance are receiving our attention and I propose to bring the Bill for consideration in this august House within the current session.

82. I had proposed to reduce the estimated fiscal deficit of 5.1 per cent in RE 2000-2001 to 4.7 per cent of GDP in BE 2001-02. The industrial slowdown experienced in both 2000-01 and the current year has reflected itself in the much lower than expected revenue collections from customs duties, excise duties and corporate income tax. The Non-Plan expenditure, however, has been kept under strict check as a consequence, Mr. Speaker, Sir, you will be pleased to hear that Non-Plan expenditure for the current year is lower by more than Rs 10,000 crore over the budgeted amount. However, mindful of the industrial slowdown, and the need for continued public investment, Plan expenditure has not only been protected but is actually higher than BE. The GDP estimate for the year has also been lowered. As a result fiscal deficit is now expected to be 5.7 per cent of GDP in the current year.

83. Putting our fiscal house in order must remain our highest priority. We have to make every effort to contain non-productive expenditure and make substantive improvements in our tax machinery so that revenue collections show higher buoyancy in coming years. I will shortly outline my plans in this regard in Part B of my speech.

84. The fastest increasing component of expenditure is that of subsidies. It is essential that they are reduced to a minimum over the next 3 to 5 years. However, access of the poor to adequate levels of nutrition through a well targetted PDS will have to be ensured along with employment generation programmes.

Expenditure Management

85. The success achieved in containing Non-Plan expenditure has encouraged me to deepen the efforts in this direction. The recommendations of the Expert Group on Government Expenditure (ERG) provide a very useful framework for controlling Government expenditure while ensuring growth. The ERG completed its work in September 2001 and submitted 10 reports covering 36 Ministries/Departments that had a total sanctioned staff of 8.65 lakh. Of the identified surplus manpower of 42,200 in these Ministries/Departments, nearly 12,200 posts are expected to be abolished by the end of March 2002. The remaining reports are at different stages of consideration. The decision to limit fresh recruitment to 1 per cent of total civilian staff strength will continue to be implemented over the next 4 years. The availability of a VRS package that has now been approved will help this effort to reduce staff strength while ensuring adequate security to the affected employees.

86. We have made efforts to contain the fertiliser subsidy by plugging inefficiencies in the production system which were earlier passed on to the government by the producers and by periodical increases in the issue prices.

The ERC has recommended that the Government should increase prices by 7 per cent every year and move towards decontrol over the next 5 years. Fertiliser prices have not been increased for the last two years. I propose a modest increase in the issue price of urea, DAP and MOP by about 5 per cent and to reduce the subsidy for SSP by Rs 50 per tonne. The prices of complex fertilisers will also be suitably modified. The Ministries of Agriculture and Chemicals and Fertilisers will notify the specific increases.

87. In a further move towards price and distribution control, the compulsory levy on sugar will be reduced from 15 to 10 per cent from March 1, 2002. Accordingly, the retail price of PDS sugar will be Rs 13.50 per kg from March 1, 2002.

88. Because of the rising cost of Postal Service, a modest increase in postal rates is being proposed.

Small Savings and Interest Rates

89. Last year I had announced the setting up of an Expert Committee headed by Deputy Governor, RBI to suggest rationalisation of administered interest rates. The Committee has given its report, which has been examined by the Government. Accordingly, I propose to take the following measures.

- ♦ Administered interest rates will now be benchmarked to the average annual yields of government securities of equivalent maturities in the secondary market. Accordingly, most administered interest rates are being reduced by 50 basis points from March 1, 2002. Such adjustments will henceforth be made annually on a non-discretionary automatic basis. The benefit of reduction in interest rates on small savings deposits will be fully passed on to the States.
- ♦ A corresponding reduction of 50 basis points will be made in the interest rate applicable to Government of India Relief Bonds. Further, a ceiling of Rs 2 lakh per year is being put on investment in these bonds.

The entire net proceeds of small savings will be transferred to State Governments beginning April 1, 2002, up from the current transfer of 80 per cent. Consequently, additional loan assistance of about Rs 10,000 crore will be available to the States along with the benefits of a lower interest rate.

State Governments will be enabled to pre-pay their high cost debt of the past from these additional resources which would be at a lower interest rate. Modalities of this pre-payment of small savings debt of State Government will be worked out in consultation with them and the Reserve Bank of India.

The interest rate on the loans portion of Central assistance to State plans is being reduced by 50 basis points.

Alignment of interest rates on GPF by the State Governments with the reduced GPF interest rates at the Centre will further reduce the interest burden of State Governments.

- ◆ Revisions are being made in the tax treatment of small savings, which will be outlined in Part B of my speech.

90. The implementation of this long sought reform in the treatment of small savings and administered interest rates is another step forward in the deregulation of interest rates in the economy that has been carried out in phases over the last 10 years. This should help in reducing the interest burden on the government and private sector alike in future.

Pension Reform

91. The present pension scheme for Government employees casts an open-ended financial burden on the Government. I had announced the appointment of a High Level Expert Group to develop a new pension scheme, based on defined contributions, for new recruits entering government service. The Expert Group has submitted its report to the Government. It has proposed a hybrid scheme that combines contributions from employees and the Union Government on matching basis, on the one hand, while committing to the employees a defined benefit as pension. The report is being considered by the Government and the new pension scheme for new recruits will be announced and implemented by June 1, 2002.

Privatization

92. With the streamlined procedure for disinvestment and privatization, I am happy to report that the Government has now completed strategic sales in 7 public sector companies and some hotel properties of the Hotel Corporation of India (HCI) and the India Tourism Development Corporation (ITDC). The change in approach from the disinvestments of small lots of shares to strategic sales of blocks of shares to strategic investors has improved the price earning ratios obtained. We expect to complete the disinvestment in another 6 companies and the remaining hotels in HCI and ITDC this year. Disinvestment receipts for the present year are estimated at Rs 5,000 crore excluding the special dividend from VSNL of Rs 1,887 crore. Encouraged by these results, I am once again taking credit for a receipt of Rs 12,000 crore from disinvestment next year.

Defence

93. Modernisation and upgradation of our Defence preparedness is an area of highest national priority. I have made a provision of Rs 65,000 crore for defence expenditure for next year. In case of need, I shall not hesitate to provide more funds for this purpose. As a measure of welfare of the defence forces and their families, and, as announced by the Prime Minister in his Independence Day speech, a major programme of housing construction for defence personnel is also being taken up.

State Fiscal Reforms

94. The challenge of fiscal management is equally acute in the case of States. We have been working jointly with the States through the Fiscal Reforms Incentive Fund set up on the recommendations of the Eleventh Finance Commission. Some State governments have taken bold measures to bring

down non-productive expenditure to improve their fiscal situation. 12 States have so far drawn up medium-term fiscal reform programmes in consultation with the Central Government in the current year and have been provided assistance from the Incentive Fund. The reform of small savings schemes together with interest rate reductions and debt swap facility that I have already mentioned will also help the States. It will be our joint endeavour to bring down the consolidated debt to GDP ratios to sustainable levels by 2005.

95. As I have mentioned earlier, we are now providing reform linked assistance to States for a number of sectors like APDRP, AIBP, URIF, RIDF for which a total amount of Rs 12,300 crore has been provided. In addition, a lump-sum amount of Rs 2,500 crore has been provided for policy reforms in sectors which are constraining growth and development. I am confident that with the joint efforts of Centre and the States we will be able to put in place programmes and policies which will remove barriers to growth, accelerate the development process and improve the quality of life of our people.

BUDGET ESTIMATES

Revised Estimates for 2001-2002

96. The revised estimates for the current fiscal year show a decrease in expenditure of Rs 10,787 crore as compared to the Budget estimates.

97. Net tax revenues for the Centre are estimated to be Rs 1,42,348 crore compared to the Budget estimate of Rs 1,63,031 crore, thereby reflecting a shortfall of Rs 20,683 crore. The major shortfall is due to lower collection of Customs and Union Excise duties due mainly to the industrial slowdown. Non tax revenue is estimated at Rs 70,224 crore, Rs 1,510 crore more than the estimated level of Rs 68,714 crore. However, disinvestment receipts, at Rs 5000 crore are much lower than the Budget estimate of Rs 12,000 crore.

Budget Estimates for 2002-2003

98. In the budget estimates for 2002-2003, the total expenditure is estimated at Rs 4,10,309 crore, of which Rs 1,13,500 crore is for Plan and Rs 2,96,809 crore for non-Plan.

Plan Expenditure

99. The budget support for Central, State and UT Plans has been placed at Rs 1,13,500 crore, an increase of Rs 18,400 crore over Budget estimates 2001-2002. This amounts to an increase of 19.35 per cent over the last year, which is the highest increase in over a decade. Gross budgetary support for the Central Plan is being enhanced from Rs 60,276 crore in the revised estimates 2001-2002 to Rs 66,871 crore in 2002-2003. Central Plan assistance to States and Union Territories in 2002-2003 is also proposed to be increased to Rs 46,629 crore from Rs 38,878 crore in the revised estimates 2001-2002. While the increase in Central Plan outlay is about 11 per cent, the increase in central assistance to state plans is nearly 20 per cent.

Non Plan Expenditure

100. Non-plan expenditure in 2002-2003 is estimated to be Rs 2,96,809 crore compared to Rs 2,65,282 crore in Revised estimates for 2001-2002. The increase in non-plan expenditure is mainly in interest payments (Rs 10,133 crores), subsidies (Rs 9,278 crore), defence (Rs 8,000 crore) and grants to State Governments (Rs 2,196 crore).

बजट 2002-2003**भाग 'ख'**

अध्यक्ष महोदय,

101. मैं अब अपने कर प्रस्तावों को सामने रखता हूँ।

102. मैंने अपने कर प्रस्ताव वर्तमान आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किए हैं। मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य मांग बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना और उत्पादकता बढ़ाना है। इनका उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना, कर संरचनाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाना तथा स्वेच्छिक अनुपालन प्रोत्साहित करना भी है।

103. पहले मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

104. महोदय, मैंने अपने पिछले बजटों में वस्तु कर ढांचे में निरन्तरता, विकृतियों, विसंगतियों और असमानताओं के मुद्दों पर ध्यान देने के कठिन प्रयत्न किए हैं। मैंने उत्पाद एवं सीमा शुल्क दोनों के संबंध में कर संरचनाओं को काफी युक्तिसंगत बनाया है। दरों की संख्या पहले से कम है और प्रणालियाँ अधिक पारदर्शी हैं। यद्यपि सेवा-कर कुछ ही सेवाओं तक सीमित है परन्तु उसमें सुदृढ़ता आई है।

105. वर्ष 2000-2001 में मैंने उत्पाद शुल्क संरचना में केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर (सेप्पैट) की दर के रूप में 16 प्रतिशत की दर शुरू की थी। पिछले वर्ष मैंने विशेष उत्पाद शुल्क की तीन दरों को कम करके 16 प्रतिशत की एक ही दर बनाई थी। शुल्क संरचना की इस युक्तिसंगतता से विवादों एवं मुकदमों में काफी कमी आई है। इससे कर निर्धारितियों द्वारा अनुपालन की लागत में भी कमी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक ऐसी प्रणाली स्थापित हुई है जो स्थिर, न्यायपूर्ण, सरल एवं कारगर है। हमें इसे केवल और सुधारने की जरूरत है।

106. मैं अनेक मदों पर 16 प्रतिशत के विशेष उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब आगे से विशेष उत्पाद शुल्क निम्नलिखित 8 मदों पर ही लगाया जाएगा:-

पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न

- » मोटर कारें
- » बहु-उपयोगी वाहन
- » बदली वाले टायर
- » वातित मृदु पेय और मृदु पेय सांद्रण
- » एयर कंडीशनर्स
- » पान मसाला और
- » खाया जाने वाला तम्बाकू एवं विविध तम्बाकू उत्पाद।

107. मैं 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की रियायती दर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो एल.पी.जी., मिट्टी तेल, आटा सी.एन.जी. और 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजनों पर लागू है, जिस पर अब 16 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर लगेगा।

108. अध्यक्ष महोदय, उत्पाद शुल्क की दरों को अब काफी कम कर दिया गया है। फिर भी अनेक छूटें अभी भी जारी हैं। अपने पिछले बजट में मैंने कुछ मदों पर 4 प्रतिशत की साधारण दर से उत्पाद शुल्क लगाया था। मैं इस दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर इस वर्ष 8 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी और मदों पर 4 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिन्हें अभी तक छूट मिली हुई थी।

109. सिगार, चुरट और तंबाकू सिगारिलोस या तंबाकू-एवजी पर, जिन्हें अभी तक छूट प्राप्त थी, 16 प्रतिशत सेनवैट लगाया जाएगा।

110. पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशासित मूल्य प्रणाली की समाप्ति को देखते हुए और एल.पी.जी. एवं मिट्टी तेल पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए, मैं पेट्रोलियम उत्पादों की शुल्क संरचना में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अधीन स्वदेशी कच्चे तेल पर लागू उपकर की दर 1 मार्च, 2002 से प्रति मीट्रिक टन 900 रुपए से बढ़ाकर प्रति मीट्रिक टन 1800 रुपए की जाएगी। मैं मोटर स्प्रिट पर लागू उत्पाद शुल्क की यथामूल्य दर 90 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इसका उत्पादन पर प्रति लीटर 6 रुपए का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, इथनाल मिले मोटर स्प्रिट पर अधिभार दर प्रति लीटर केवल पांच रुपए पच्चीस पैसे होंगे।

111. अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में भारतीय वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साधन है। वर्ष 2004 तक "मल्टी फाइबर" करार को क्रमिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। घरेलू बाजार पहले ही खोल दिया गया है। हमारे वस्त्र उद्योग को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करना है।

112. मैंने वस्त्र उद्योग के लिए प्रोत्साहनों का एक विशिष्ट पैकज तैयार किया है।

113. मैं धागे पर उत्पाद शुल्क की दरें बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। सूती लच्छी वाले धागे को उत्पाद शुल्क से छूट है। हथकरघा बुनकरों को ही लक्षित लाभ मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिए मैं एक तरफ तो लच्छीदार धागे (हैंक यार्न) को 8 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूँ और दूसरी तरफ उनके द्वारा खरीदे गए लच्छीदार धागों के मूल्य पर उपयुक्त सब्सिडी प्रदान करता हूँ। इससे कर अपवृत्ति समाप्त होगा और सब्सिडी संबंधी लक्ष्य बेहतर ढंग से निर्धारित किए जा सकेंगे। कपड़ा मंत्रालय इस सब्सिडी स्कीम के विवरणों की घोषणा करेगा।

114. बुनकरों को "सेनवैट क्रेडिट स्कीम" का लाभ प्रदान करने के लिए मैं "ग्रे-फंक्चर्स" (धूसर वस्त्र) बुनकरों को वैकल्पिक आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं दुनाई क्षेत्रक को भी ऐसा ही विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

115. अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा कर सकता हूँ कि मैंने उत्पाद शुल्क संरचना में 16 प्रतिशत की "सेनवैट" दर शुरू की है। परन्तु मैं इसके अपवादस्वरूप वस्त्र उद्योग के मामले में 4 प्रतिशत की कटौती प्रदान कर रहा हूँ। वस्त्रों, सिले-सिलाए वस्त्रों और परिधानों पर उत्पाद शुल्क की दर 12 प्रतिशत होगी। यह विशेष छूट 28.2.2005 तक जारी रहेगी। परन्तु औद्योगिक परिधानों पर 16 प्रतिशत का शुल्क जारी रहेगा।

116. इस समय स्वतंत्र रूप से वस्त्र तैयार करने वालों के लिए हाथ से वस्त्र तैयार करने के मामले में उत्पाद शुल्क से छूट है भले ही विद्युत का उपयोग सूती वस्त्र के मामले में 12 विनिर्दिष्ट प्रोसेस (प्रक्रियाओं) के लिए और व्यक्ति द्वारा निर्मित वस्त्रों के मामले में 7 विनिर्दिष्ट प्रोसेस के लिए किया गया हो। मैं इस छूट को 3 प्रक्रियाओं अर्थात् सफाई करने, निचोड़ने और कैलेंडरिंग के लिए सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

117. मैं, स्वतंत्र विद्युत प्रोसेसर्स के लिए मिश्रित लेवी स्कीम समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ क्योंकि यह मेरे द्वारा प्रस्तावित कम की गई शुल्क दर के अनुकूल नहीं है।

118. मेरे बजट प्रस्तावों से हथकरघा क्षेत्रक प्रभावित नहीं है। हथकरघा वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क छूट जारी है। मैं अब हथकरघा वस्त्रों के लिए भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ बशर्ते हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इसका प्रमाणन किया गया हो।

119. वस्त्र उद्योग द्वारा अपना आधुनिकीकरण करने और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए मैं आटोमैटिक शटल रहित लूम पर उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूँ। मैं विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी तथा विनिर्दिष्ट रेशम की रीलिंग (चरखी पर लपेटना), बुनाई एवं ट्विस्टिंग (बटाई) मशीनरी पर उत्पाद शुल्क की छूट का भी प्रस्ताव करता हूँ। ऐसी मशीनरी पर सीमा शुल्क भी 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं विनिर्दिष्ट जूट मशीनरी को भी उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इस पैकेज से वस्त्रोद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होगा।

120. मेरे प्रस्ताव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए उत्पाद शुल्क ढाँचे में विशेष छूट शामिल है। दिनांक 1 मार्च, 2002 से इन सभी रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों पर अन्यथा पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू उत्पाद शुल्क की सामान्य दर का आधा उत्पाद शुल्क प्रभार्य होगा।

121. पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर हवाई यात्रा के लिए अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर से छूट प्राप्त है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों तक और वहां से की जाने वाली हवाई यात्रा पर इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

122. इस समय चाय उद्योग अनेक कारणों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। चाय उत्पादकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए मैं चाय पर उत्पाद शुल्क प्रति किलो 2 रुपए से घटाकर प्रति किलो 1 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

123. हमें "एचआईवी-एड्स" के खतरे का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना है। मैं 1 मार्च, 2002 से "एड्स-रोधी" विनिर्दिष्ट दवाओं पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

124. विनिर्दिष्ट शीत श्रृंखला उपस्करों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। मैं फलों और सब्जियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3 और उपस्करों को इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

125. लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए उत्पाद शुल्क की छूट ग्रेनाइट के लिए भी लागू है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह संगमरमर के लिए उपलब्ध नहीं है, मैं इस छूट को ग्रेनाइट से भी वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

126. वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित उत्पाद शुल्क मूल्यांकन की योजना ने नाटकीय रूप से मूल्यांकन संबंधी विवादों को सुलझाया है। मैं इस वर्ष इस योजना को मदों की 9 और श्रेणियों के लिए लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे इन मदों की श्रेणियों की संख्या बढ़कर 92 हो जाएगी।

127. अध्यक्ष महोदय, और अधिक सेवाओं पर कर लगाने को न्यायसंगत ठहराने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष मेरा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा-कर लगाया जाए:

- * जीवन बीमा, जिसमें बीमा संबंधी सहायक सेवाएं भी शामिल हैं।
- * अंतर्देशीय कार्गो संचालन।
- * भंडारण और भंडागारण (कृषि उत्पादों तथा शीत-भंडारण को छोड़कर)।
- * समारोह प्रबंधन।
- * रेल यात्रा एजेंट।
- * हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर।
- * ब्यूटी पार्लर।
- * फैशन डिजाइनर्स।
- * केवल आपरेटर्स।
- * ड्राइक्लीनिंग सेवाएं।

128. सेवा-कर बैंकों तथा बैंकिंग-भिन्न वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं पर भी लागू होता है। मैं उन निगमित निकायों पर भी सेवा-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, जो ऐसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं।

129. इन सेवाओं पर यह कर अधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे।

130. हाल ही की घटनाओं से हमारे पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दिसम्बर, 2001 में मैंने होटलों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सेवा-कर छूट की घोषणा की थी। यह छूट 31 मार्च, 2002 को समाप्त होनी है। मैं इस छूट को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. महोदय, अब मैं सीमा-शुल्क संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

132. सदन को याद होगा कि मैंने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि मैं सीमा-शुल्क की उच्च दर को तीन वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर कम करके 20 प्रतिशत पर लाऊंगा। मैंने यह भी कहा था कि अगले बजट के लिए इसकी कार्यप्रणाली समय पर तैयार की जाएगी। कार्यप्रणाली की सिफारिशें करने के लिए तदनुसार मैंने एक अंतर-मंत्रालयीन कार्य दल का गठन किया था। इस दल ने इस वर्ष के बजट में यह शुरु करने के लिए इसकी रूपरेखा सुझाई है। दल की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, मैंने निर्णय लिया है कि वर्ष 2004-05 तक सीमा-शुल्क की केवल दो मूल दरें होंगी अर्थात् 10 प्रतिशत की दर, जिसके अंतर्गत सामान्य कच्चा माल, मध्यवर्ती माल और संघटक होंगे और 20 प्रतिशत की दर, जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से तैयार उत्पाद शामिल होंगे। विद्यमान दरों को विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं अथवा कृषि उत्पादों के लिए उच्चतर शुल्कों के अपवाद सहित इन दो मूल दरों में समायोजित और सम्मिलित किया जाएगा। सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार मैं 35 प्रतिशत की अधिकतम दर को कम करके इस वर्ष 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कुछ वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

133. हमारा इस्पात उद्योग मांग की मन्दी से प्रभावित हुआ है और इसे काफी क्षति पहुंची है। इसके उत्पादन लागत को कम करने के लिए मैं कई ताप-सह मृत्तिका कच्ची सामग्रियों पर

सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें प्राकृतिक गैफाइट चूर्ण, सिलिकन धातु, निसादित अल्युमिना, पिघला हुआ जर्कोनिया और बोरॉन कार्बाइड शामिल हैं। मैं 24 इंच व्यास से अधिक के गैफाइट ब्लेक्ड्रोड पर शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

134. विखंडन के लिए आयातित जहाजों पर प्रतिकाशी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क के साथ 5 प्रतिशत सीमा-शुल्क प्रभावी होता है। मैं विखंडन के लिए जहाजों पर बुनियादी शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके और उन्हें प्रतिकाशी शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देकर इसमें राशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित बेलित उत्पाद और जहाज के विखंडन से उत्पादित सरते उत्पादों के बीच विसंगति कम करने के लिए है।

135. इस्पात उद्योग को पुराने और त्रुटिपूर्ण इस्पात के सरते मूल्य पर आयातों द्वारा नुकसान होता है। उनकी चिंता पर ध्यान देने के लिए मैं पुराने और त्रुटिपूर्ण इस्पात पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 40 प्रतिशत की आवद्ध दर तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. अलौह धातुओं का प्रयोग उद्योग के विभिन्न खंडों द्वारा कई तरह के अनुप्रयोगों में होता है। मैं तांबा, जस्ता और सीसा पर सीमा-शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अल्युमीनियम और टिन पर भी सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

137. वर्ष 2000-2001 के लिए निर्यात-आयात नीति में मेरे सहयोगी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्कीम घोषित की है, जिसका आशय निर्यात उत्पादन के लिए एक स्थान में व्यापक सुविधाएं प्रदान करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र शुल्क मुक्त उपस्कर, कच्ची सामग्रियां, रांघटक आदि, चाहें वे आयातित हों अथवा स्थानीय रूप से खरीदे गए हों, प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी छूट का लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उसमें अवस्थित यूनिटों दोनों के विकासकर्ताओं पर लागू होगा।

138. विश्व-स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैं पत्तनों और विमानपत्तनों के लिए निर्दिष्ट उपस्करों पर सीमा-शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

139. नागर विमानन क्षेत्रक द्वारा रामना की जा रही कठिनाइयों के दृष्टिगत मैं हवाईजहाजों, हेलीकॉप्टरों, ग्लाइडरों, हवाईजहाजों के अनुरूपकों तथा उनके पुर्जों और कच्ची सामग्रियों पर शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

140. अध्यक्ष महोदय, भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस सदन को याद होगा कि वर्ष 1998 में मैंने घोषणा की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क प्रणाली 2003 तक पहले ही प्रभावी और कार्यान्वित होगी। तथापि, स्थानीय विनिर्माताओं ने मुझसे बलपूर्वक आग्रह किया है कि इसे वर्ष 2005 से प्रभावी किया जाए। यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती पूरी करने के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करेगा। मैंने उनकी मांग स्वीकार करने का निर्णय लिया है। देशी उद्योग को सहायता के एक उपाय के रूप में मैं कई हार्डवेयर निविष्टियों पर सीमा-शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और कतिपय पूंजीगत सामग्रियों पर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी के कतिपय मर्दों पर शुल्क विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के अनुसार 10 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत तक कम की जाएगी।

141. सेलूलर फोन का प्रयोग दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है परन्तु अनधिकृत माध्यमों से आयात एक चिंता का विषय है। इसलिए मैं सेलूलर फोन और पेजर्स को प्रतिकाशी

शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, बुनियादी सीमा-शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

142. महोदय, मैंने सदन को बारम्बार आश्वस्त किया है कि किसानों के हित संरक्षण के लिए हमारे सीमा-शुल्क टैरिफ को उपयुक्त स्तरों पर स्थिर किया जाएगा। मैंने अपने पिछले वजट में चाय, कॉफी, कोपरा और नारियल तथा सूखे नारियल पर सीमा-शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया था। इस वर्ष, मैं चाय और कॉफी पर सीमा-शुल्क 100 प्रतिशत और प्राकृतिक रबड़, खसखस, काली मिर्च, लौंग और इलायची पर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं दालों पर भी शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

143. हमारे किसानों को नई और सक्षम प्रांद्यांगिकी अधिग्रहीत करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मैं कृषि मशीनरी और उपकरणों पर सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. कई औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है। मैं, कैंसर और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त और अन्य औषधियों को पूर्णतः छूट प्राप्त औषधियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। जापानी मस्तिष्क शोथ से प्रतिरक्षण के लिए टीके भी सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त होंगे। यह सूचित किया गया है कि इस समय सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त कतिपय औषधियों का निर्माण अब देश में किया जाता है। इन औषधियों के घरेलू विनिर्माताओं को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इन औषधियों पर 5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

145. भारत में बड़ी संख्या में मधुमेह के रोगी हैं। उन्हें बारम्बार रक्त शर्करा की जांच करानी होती है। उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के लिए मैं ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

146. यौक्तिकीकरण के उपाय के रूप में और विसंगति दूर करने के लिए मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अधीन बेचे जाने वाले मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

147. विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैं तारामंडल (प्लेनेटोरियम) उपकरणों, पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमाशुल्क घटाकर 15 प्रतिशत करने और उन्हें सीवीडी और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

148. भारत के पास "सार्क" देशों के लिए टेलीविजन चैनलों हेतु एक संयोजक केन्द्र बनने की तकनीकी दक्षता है। प्रतिस्पर्धी लागतों पर अत्याधुनिक संयोजक सुविधाओं के संवर्धन के लिए मैं कतिपय भू-केन्द्र उपकरणों और स्टूडियो उपकरणों पर सीमाशुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

149. मैं सीमेंट और खंगर पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह घरेलू कीमते नियंत्रणाधीन रखने में सहायक होगा।

150. विश्व व्यापार संगठन के अधीन चालू वर्ष के लिए आयातित शराब पर सीमाशुल्क 182 प्रतिशत पर आबद्ध है। तदनुसार मैं इन मदों पर सीमाशुल्क 210 प्रतिशत से घटाकर 182 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं शराब और मदिरा पर लागू प्रतिकारी शुल्क की दरें प्रति डिब्बा 25 अमरीकी डालर तक के मूल्य वाली शराब और मदिरा के लिए 75 प्रतिशत और अन्यो के लिए 50 प्रतिशत तक युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

151. निवासस्थानों के स्थानान्तरण पर विदेश से लांटेन वाले यात्रियों को 35 प्रतिशत की एकसमान दर पर सीमाशुल्क के भुगतान पर व्यक्तिगत प्रयोग की कतिपय मदों को लाने की अनुमति दी जाती है। मैं इस दर को घटाकर 30 प्रतिशत करने और लैपटॉप कम्प्यूटर्स, सुवाह्य फोटोकॉपी मशीन, डिजीटल वीडियो डिस्क प्लेयर, वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर जैसी कुछ और मदों को मदों की पात्र सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के अधीन अनुमेय मदों के मूल्यों की समग्र सीमा भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है।

152. मैं ऐसी कुछ मदों, जिन्हें इस समय छूट प्राप्त है, पर 5 प्रतिशत का सामान्य सीमाशुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कतिपय अन्य मदों जिनपर इस समय 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है, पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

153. मैंने छोटी प्रकृति के कुछ अन्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है। मैंने सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों, जो वित्त विधेयक में विहित हैं, के संबंध में कुछ विधायी परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया है। मैं उन पर ब्यौरेवार चर्चा करके सदन का समय नहीं लेना चाहता।

154. अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क ढांचे को काफी सरल बनाया गया है। इन परिवर्तनों, जिनका मैंने प्रस्ताव किया है, 16 प्रतिशत सैनवेट से राजस्व प्राप्ति मूल्यानुसार शुल्क से कुल राजस्व का 85 प्रतिशत से भी अधिक होगी। आगामी दो वर्षों में इसे कम करके एक अर्थात् 16 प्रतिशत किया जा सकता है। सीमाशुल्क टैरिफ में भी तीन वर्षों के समय में केवल दो मूल दरें होंगी।

155. अपने पिछले बजटों में मैंने कार्यविधियों को सरल बनाने का भी काफी प्रयास किया है। तथापि, कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे कर प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारी कर प्रणाली को र्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहित करने, करदाताओं को सक्षम सेवा प्रदान करने, अनुत्पादक कार्य हटाने और दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। विवेकाधीन शक्तियों को नियम-आधारित कार्यतंत्र से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। कर प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर उनकी संपूर्णता में जांच करने की आवश्यकता है। मैं इन पहलुओं का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

156. उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से वर्ष में लगभग 6700 करोड़ रुपए राजस्व लाभ होने का अनुमान है। सीमा शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से लगभग 2200 करोड़ रुपए राजस्व हानि होने का अनुमान है। तथापि, मैं अप्रत्यक्ष कर राजस्व में घट-बढ़ का पूर्वानुमान करता हूँ और यह अनुमान करता हूँ कि अगले वर्ष कुल संग्रहण 1,43,702 करोड़ रुपए होगा।

157. उत्पाद तथा सीमा शुल्कों में किए जाने वाले परिवर्तनों को प्रभावी रूप देने हेतु जारी अधिसूचनाओं की प्रतियों को यथा-समय संसद के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

158. अब मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

159. पिछले कई वर्षों में वैयक्तिक आय कर दरें 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तथा निगम कर 35 प्रतिशत रही हैं। वे युक्तिसंगत हैं और इसलिए मैंने अपने पिछले चार बजटों में उनमें परिवर्तन नहीं किया है। इस वर्ष भी मेरा उनमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

160. साथ ही, विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मैं कई क्षेत्रों को रियायतें प्रदान कर रहा हूँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है और जो पुनरुद्धार तथा विकास की सम्भावनाएं रखते हैं। अब मैं उनका उल्लेख करता हूँ।

161. मैंने पहले ही औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश के सम्बन्ध में प्रोत्साहन मुहैया कराने की आवश्यकता बताई है। ऐसे निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु मैं नई औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु 1 अप्रैल, 2002 को अथवा उसके बाद अधिग्रहित नए संयंत्र और मशीनरी के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत की दर पर अथवा मौजूदा इकाइयों की संस्थापित क्षमता के विस्तार हेतु कम से कम 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति प्रदान करता हूँ।

162. विदेशी कम्पनियों तथा घरेलू कम्पनियों के संबंध में लागू निगम कर दरों के मध्य विषमता है। यह विषमता विगत में आंशिक रूप से अधिभार जैसे कतिपय करारोपणों के कारण देखने को मिली, जो घरेलू कम्पनियों के सम्बन्ध में लागू थी लेकिन विदेशी कम्पनियां इससे प्रभावित नहीं थी। इसे दूर करने के लिए मैं विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में लागू दर को 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

163. आर्थिक विकास में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस निरन्तर सहायता दिए जाने की जरूरत है। लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को अपने संसाधनों को बढ़ाने तथा लघु क्षेत्र को रास्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु मैं "सिडबी" द्वारा जारी बांडों में निवेश की गई राशि पर आय कर अधिनियम की धारा 54डग के तहत पूंजी लाभ छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

164. वर्ष 2000-2001 के बजट में, मैंने लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी स्कीम आरंभ करने की घोषणा की थी। तदनुसार लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी न्यास का गठन किया गया है। मैं इस न्यास को आयकर से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

165. पिछले चार वर्षों में आवास क्षेत्रक पर निरंतर जोर देते हुए, मैं स्व-अधिग्रहित भवनों के सम्बन्ध में जब तक वित्तीय वर्ष के अन्त से जिसमें कि पूंजी ऋण लिया गया था, तीन वर्षों के भीतर अधिग्रहण अथवा निर्माण की कार्यवाई पूर्ण होने तक, आवास ऋणों पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, भले ही जहां ऐसे भवन 31 मार्च, 2003 के बाद अधिग्रहित अथवा निर्मित किए गए हों। आवास क्षेत्रक में निवेश को और प्रोत्साहन देने हेतु, मैं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों पर आयकर अधिनियम की धारा 54डग में उपलब्ध पूंजी लाभ छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

166. भारत में नौवहन उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी है तथा यह और विकास करने में समर्थ है। वर्ष 2000-2001 के अपने बजट में मैंने नौवहन कम्पनी के अर्जित सम्पूर्ण लाभ पर कटौती की व्यवस्था की थी बशर्ते कि कटौती की गई यह राशि प्रारक्षित निधि में रखकर नए पोतों की खरीद हेतु उपयोग में लाई जाए तथापि, ऐसी प्रारक्षित निधि में अन्तरित की जा सकने वाली राशि का कुल योग कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी की राशि की दुगुनी राशि तक सीमित है। मैं इसे शेयर प्रीमियम प्रारक्षित निधि और सामान्य प्रारक्षित निधि को भी शामिल करते हुए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रारक्षित निधि को वही लाभ का आकलन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इस प्रकार नौवहन कम्पनियां न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के दायरे से बाहर होंगी।

167. वर्तमान में, बैंकों को अपने अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान के प्रति कुल आय का 5 प्रतिशत तक कटौती प्रदान करने की अनुमति दी गई है। बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु, मैं इस भत्ते को कुल आय के 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999-2000 के अपने बजट में, मैंने बैंकों को उनके गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का जो लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस की स्थिति के अनुसार हानि अथवा संदिग्ध परिसम्पत्तियों की श्रेणी में आते हैं, 5 प्रतिशत तक कटौती करने का विकल्प प्रदान

किया था, मैं इस वैकल्पिक कटौती को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ और साथ ही मैं सरकारी वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हानि अथवा संदिग्ध परिसम्पत्तियों के लिए 10 प्रतिशत तक इसी प्रकार की वैकल्पिक कटौती की अनुमति प्रदान करता हूँ।

168. यह निरन्तर मांग रही है कि औद्योगिक उपक्रमों की कम्पनियों के विलयन के मामलों में अग्रणीत लाभ तथा पिछली हानियों की प्रतिपूर्ति को और भी क्षेत्रों में लागू किया जाए। विशेष रूप से, दूरसंचार क्षेत्र, तीव्र सुदृढीकरण तथा विस्तार के चरण में है। इसकी प्रगति को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं इस लाभ को दूरसंचार-सेवाएं उपलब्ध कराने वाली तथा धारा 80-झक के तहत कटौती हेतु पात्र कम्पनियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस लाभ के विस्तार की जांच वित्तीय सेवा क्षेत्र सहित सेवा क्षेत्र में रत अन्य कम्पनियों में करने हेतु एक विशेषज्ञ दल के गठन का भी प्रस्ताव करता हूँ।

169. पर्यटन क्षेत्र को और अधिक राजकोषीय राहत उपलब्ध कराने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- ❖ अब से होटलों पर व्यय कर केवल कमरे के शुल्कों पर लागू होगा तथा प्रति दिवस 2,000 रुपये के मौजूदा प्रारम्भिक की तुलना में केवल वही देय होगा जहां ऐसे शुल्क प्रति दिवस 3,000 रुपये अथवा इससे अधिक हैं।
- ❖ होटल अथवा पर्यटन आपरेटरों से अर्जित विदेशी मुद्रा अर्जनों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 80जजघ के तहत उपलब्ध कटौती को धारा 80जजग के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध कटौती के अनुरूप करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
- ❖ ऐसी इकाइयों द्वारा जो बड़े सम्मेलन केन्द्रों को स्थापित तथा संचालित करती हैं, अर्जित लाभों की 50 प्रतिशत की कटौती 5 वर्ष के लिए 80-जख के तहत प्रदान की जाएगी।

170. मैंने अपने भाषण के भाग क में मनोरंजन उद्योग की महत्ता पर बल दिया है। इस तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए मैं महानगरीय भिन्न करबों में बहुविध थियेटर्स का निर्माण करने वाली व चलाने वाली इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों पर अगले पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

171. हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और पुनरुज्जीवन के उपाय के रूप में मैं निम्नकोटि की वन-भिन्न भूमि पर नरम लकड़ी के पौधारोपण की परियोजनाएं चलाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित किसी कंपनी या संस्था को भुगतान की गई राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, की धारा 35कग के अंतर्गत कर कटौती के माध्यम से प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ। इस धारा के अंतर्गत कटौती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनीकरण के लिए भुगतानों के संबंध में भी उपलब्ध होगी।

172. पिछले वर्ष धारा 10(23ग) के अंतर्गत दावा करने वाले धर्मार्थ एवं धार्मिक न्यासों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं के मामले में पारदर्शिता का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए मैंने उनके लेखे किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने की अपेक्षाओं वाले प्रावधान आरंभ किए थे, यदि उनकी प्राप्तियां एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से बढ़ जाती हैं। मुझे समाज विरोधी तत्वों द्वारा ऐसी सूचना के दुरुपयोग की संभावना इंगित करते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों के दृष्टिगत, मैं इस अपेक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन न्यासों और संस्थाओं के संबंध में कतिपय प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव भी करता हूँ ताकि उनकी आय के किसी भाग के संग्रहण की अनुमति सिर्फ अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए हो और यह स्पष्ट करता हूँ कि अंतर-न्यास दान केवल या तो संग्रह से किए जाएं या चालू वर्ष की आय से किए जाएं।

173. पिछले वर्ष गुजरात में आए भूकंप के बाद मैंने कतिपय अनुमोदित धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों को 100 प्रतिशत कर कटौती की स्वीकृति दी थी जिसे 31 मार्च, 2002 तक राहत कार्य में लगाना था। चूंकि, ऐसे राहत कार्य अनेक क्षेत्रों में चल रहे हैं मैं ऐसे दान के उपयोग के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2002 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2003 करने का प्रस्ताव करता हूं।

174. पिछले वर्ष मैंने घरों और कारों के सिवाय, जहां सरलता के लिए विभिन्न कसौटियां अपनाई जाती हैं, नियोक्ता को उनकी लागत के आधार पर पूर्वापेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नियमों को तर्कसंगत बनाया था। न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों का बोझ कम करने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि उन कर्मचारियों के मामले में जिनका कर योग्य वेतन, पूर्वापेक्षाओं को छोड़कर, 1,00,000 रुपये तक है, मूल्यांकन वर्ष 2002-2003 के लिए कोई पूर्वापेक्षाएं मूल्यांकित नहीं की जाएंगी। परवर्ती वर्षों के लिए मैं नियोक्ता को कर्मचारियों की तरफ से पूर्वापेक्षाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रस्ताव करता हूं।

175. आयकर अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत वेतन के बकाया की प्राप्ति के कारण किसी एक वर्ष में लागू अतिरिक्त कर भार के मामले में कर-राहत की व्यवस्था की गई है। कल्याण उपाय के रूप में मैं इस राहत की अनुमति उन मामलों में भी देने का प्रस्ताव करता हूं जहां परिवार पेंशन बकाया में प्राप्त हुई है।

176. मेरे पूर्ववर्ती बजटों में मेरे द्वारा लाए गए करदाता अनुकूल उपायों की निरंतरता में, मैं आयकर अधिनियम के अध्याय XXXC के उपबंधों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो किसी अवल संपत्ति के अंतरण के पंजीकरण से पहले समुचित प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।

177. महोदय, आयकर अधिनियम में वर्तमान में उपबंधित कुछ छूटें और कटौतियां व्यर्थ हो गई हैं और संतुलित कर प्रशासन के सामंजस्य में नहीं हैं, जो हमारे भारत में हैं। दसवीं योजना के लिए कर नीति और कर प्रशासन संबंधी सलाहकार दल ने ऐसी अनेक छूटों की समाप्ति की अनुशंसा की है। मैंने इस दल की प्रत्येक अनुशंसा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इन में से कुछ छूटें तो वास्तव में अनावश्यक हैं। अतः मैं इन छूटों को वापस लेने या बंद करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी और आवश्यकता नहीं है।

178. इस सलाहकार दल ने शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं सहित अनुमोदित या अधिसूचित निकायों या संस्थाओं की आय को स्वीकृत अनेक छूटों को समाप्त करने की भी अनुशंसा की है। मैं नहीं सोचता कि इन संस्थाओं और निकायों, जो सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, को प्राप्त छूटों को वापस लिया जाए। तथापि, मैं ऐसे सभी निकायों और संस्थाओं से इस अपेक्षा का प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक वर्ष की आय की विवरणियां दर्ज करें ताकि आवधिक सत्यापन में सक्षम हुआ जा सके कि क्या निर्धारित शर्तों, जो मुख्यतया आय के प्रयोग से संबंधित हैं, का पालन किया जा रहा है और यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्थाओं के अनुमोदन या अधिसूचना को वापस लेने में सक्षम हो सके यदि वे किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं।

179. पिछले वर्ष मैंने नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी द्वारा अर्जित आय को कर-छूट की अनुमति वापस ले ली थी, क्योंकि ये संस्थाएं पुरानी हो चुकी हैं और वाणिज्यिक स्तर पर कार्य कर रही हैं। इसी कारण से मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रसार भारती और तेल उद्योग विकास बोर्ड को अनुमत छूट को इस वर्ष वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

180. मूल्यहास से संबंधित नियमों में वर्षों से किए गए विभिन्न संशोधनों ने विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों की ऐसी अनेक दरें उत्पन्न कर दी हैं। इन दरों के साथ चलने की प्रासंगिकता

और आवश्यकता तथा क्या उन्हें 60 प्रतिशत की अधिकतम दर तक घटा दिया जाए, यह खुली चर्चा का विषय होना चाहिए। सुसंगत त्वाँरे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। व्यक्त किए गए विचारों का ध्यान में रखते हुए, मूल्यहारा दरों की सशोधित अनुरूची अधिसूचित की जाएगी।

181. लाभार्थों और यूनितों से आय के कराधान की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, कंपनी या म्यूचुअल फंड 10 प्रतिशत कर का भुगतान करती है और आय प्राप्तकर्ता का छूट प्राप्त है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आय पर ही कर नहीं लगाती जिससे यह संबंधित नहीं है; बल्कि यह उसके माध्यस्थ स्तर के भी प्रतिकूल है जो म्यूचुअल फंड की मूल भावना है। वर्तमान नीति में एक अंतर्निहित असमानता भी है जो उच्च-आय समूहों में व्यक्तियों को उन पर लागू दरों की तुलना में काफी कम दरों पर कर लगाने की अनुमति देती है। ये मुद्दे पिछले चार वर्षों से मेरी परेशानी का कारण रहे हैं और मैं अब सतुष्ट हूँ कि विद्यमान प्रणाली को अवश्य ही जाना होगा। अतएव, मैं कंपनियों और म्यूचुअल फंडों पर उनके द्वारा वितरित लाभार्थ या आय पर 10 प्रतिशत वितरण कर समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से आगे ऐसे आय प्राप्तकर्ताओं पर लागू दरों पर, कर लगंगा और 10 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर कटौती की शर्त के अधीन होगा। परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए ऐसी आय प्राप्त करने वाली कंपनियाँ, उनके द्वारा वितरित लाभार्थों के रूप में धनराशि के लिए कटौती का दावा करने की पात्र होंगी। मेरे द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों के इक्विटी वाले फंडों को दिए गए मेरे समर्थन को जारी रखते हुए, ऐसे फंडों के यूनिट धारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान प्राप्त आय पर वर्तमान के 10 प्रतिशत की दर पर ही कर लगंगा।

182. सभी व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों को अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखने को प्रोत्साहित करने के लिए इस समय आय कर अधिनियम की धारा 88 में विनिर्दिष्ट कुछ बचत पत्रों में निवेश की गई राशि पर 20 प्रतिशत की कर राहत प्रदान की जाती है। तथापि, अधिक सीमा तक कर अदा करने वालों को विभिन्न लिखतों के माध्यम से बचत करने के लिए राजकोपीय प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं 20 प्रतिशत की मौजूदा दर पर इस कर राहत को केवल 1,50,000 रुपए तक की कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूँ। 1,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों को निवेश की गई राशि पर अब केवल 10 प्रतिशत की राहत प्राप्त होगी तथा 5 लाख रुपए से अधिक कर-योग्य आय पर अब कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, 1 लाख रुपए तक की कर-योग्य वेतन आय पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही, जब कि निवेश की अर्हक राशियों पर मौजूदा सीमाएं अभी जारी रहेंगी, मैं कानून के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जब तक निवेश की राशि वर्ष की कर-योग्य आय से कम है, तब तक वर्ष के दौरान किसी भी समय किए गए निवेश पर यह छूट दी जाती रहेगी।

183. इस समय, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के कुछ वर्गों को कर से छूट प्राप्त है। मेरा प्रस्ताव है कि इस संबंध में कतिपय राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय महत्व के अधिसूचित किए जाने वाले संस्थानों के कर्मचारियों को भी यह छूट प्रदान की जाए।

184. मैं कुछ प्रणालीगत परिवर्तन भी कर रहा हूँ, जिन्हें वित्त विधेयक में शामिल किया गया है।

185. आयकर विभाग द्वारा "सम्पर्क" नामक एक योजना को आरम्भ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कर दाता इंटरनेट के माध्यम से जानकारी और फार्म प्राप्त कर सकेंगे। विभाग

द्वारा प्रयोक्ता-अनुकूल साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कर दाता अपनी आय संबंधी विवरणियां तैयार कर सकेंगे।

186. सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली प्रयोग बहुत सीमा तक स्थायी खाता संख्या (पैन) संबंधी आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करने पर निर्भर करेगी। मैं ऐसे सभी मामलों, जिनमें विनिर्दिष्ट लेन-देनों संबंधी दरतावेजों में फर्जी पैत्र संख्या का उल्लेख किया गया हो, के संबंध में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के लिए आय कर अधिनियम में एक विशेष प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखता हूं।

187. 1998 में मैंने मोटर कार की खरीद अथवा बिक्री तथा होटल और रेस्टोरेंट में किए गए व्यय जैसे कुछ उच्च-मूल्य वाले लेन-देनों का निर्धारण किया था जिसके अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। मेरा प्रस्ताव है कि आय कर नियमों के नियम 114-ख के अंतर्गत उल्लिखित लेन-देनों की इस सूची में विदेश यात्रा पर 25,000 रुपए से अधिक राशि नकद खर्च करने, 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि के बैंक ड्राफ्ट खरीदने तथा किसी भी बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि जमा करने को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मेरा ऐसे नियम लागू करने का भी प्रस्ताव है कि नियम 114-ख में निर्दिष्ट किसी भी लेन-देन, जो नकद रूप से किया जाए, की सूचना आय कर विभाग को एक निश्चित अवधि के भीतर दे दी जानी चाहिए।

188. महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की विंता हमारे लिए सर्वोपरि है। इसकी कीमत हम सभी को मिल कर वहन करनी होगी। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि 60,000 रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों को छोड़ कर, कर दाताओं के सभी वर्गों पर 5 प्रतिशत की दर से एक-समान मामूली अधिभार लगाया जाए। गुजरात भूकम्प के परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष लगाए गए 2 प्रतिशत अधिभार को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए इससे केवल 3 प्रतिशत के अतिरिक्त निवल कर का प्रभाव पड़ेगा। मैं आय कर अधिनियम की धारा 10क तथा धारा 10ख के अंतर्गत कतिपय यूनियों का प्रदत्त निर्यात लाभ की 100 प्रतिशत कटौती को कम करके मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 के लिए 90 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

189. महोदय, अंत में, इस बजट में प्रत्यक्ष करों से संबंधित मेरे द्वारा रखे गए प्रस्तावों से 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी जिसमें 2,750 करोड़ रुपए का अधिभार घटक भी शामिल है। मेरा अनुमान है कि 2002-2003 में प्रत्यक्ष कर राजस्व से 91,585 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

190. अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि इन प्रस्तावों से केंद्र को कुल 1,72,965 करोड़ रुपए की कर राजस्व प्राप्तियां होंगी तथा राजकोषीय घाटा 1,35,524 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत होगा।

191. अध्यक्ष महोदय, यह बजट सुधार प्रक्रिया के समेकन, विस्तारीकरण और गहनिकरण के लिए है। यह विकास के प्रति समर्पित बजट है। यह भारत के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राज्यों के साथ भागीदारी को और संबंधित करने वाला बजट है।

192. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस महान सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूं।

डी. स्वरूप, अपर सचिव

Budget 2002-2003

PART B

101. Sir, I now present my tax proposals.

102. I have formulated my tax proposals against the backdrop of the current economic slow-down. My tax proposals are intended to revive demand, promote investment, accelerate economic growth and enhance productivity. They are also aimed at widening the tax base, rationalization and simplification of tax structures and encouraging voluntary compliance.

103. I present my indirect tax proposals first.

104. Sir, in my earlier budgets I have made strenuous efforts to address the issues of cascading, distortions, anomalies and inequities in the commodity tax structure. I have achieved significant rationalization of tax structures relating to both excise and customs duties. The number of rates are few, and procedures more transparent than before. The service tax, though confined to limited number of services, has gained ground.

105. In 2000-2001, I had introduced the rate of 16% as the rate of Central Value Added Tax (CENVAT) in the excise duty structure. Last year, I had reduced the three rates of special excise duty to a single rate of 16%. This rationalization in the duty structure has considerably reduced disputes and litigation and the cost of compliance to the assessees. Above all, it has put in place a system, which is stable, just and rational. We only need to refine it further.

106. I propose to abolish the 16% special excise duty on a number of items: Henceforth, the special excise duty shall be confined to the following 8 items only:

- Polyester Filament Yarn
- Motor cars
- Multi Utility Vehicles
- Tyres for replacement

- Aerated soft drinks and soft drink concentrates
- Air conditioners
- *Pan Masala*, and
- Chewing Tobacco & miscellaneous tobacco preparations

107. I propose to do away with the concessional rate of 8% excise duty applicable to LPG, kerosene, auto CNG and diesel engines upto 10 HP which will now attract the CENVAT rate of 16%.

108. Mr. Speaker Sir, the rates of excise duty have now been considerably moderated. However, several exemptions still continue. In my last budget I had imposed excise duty at a moderate rate of 4% on a few items. I propose to increase this rate from 4% to the next slab of 8% this year. Simultaneously, I propose to impose excise duty at 4% on a few more items, which have remained exempted so far.

109. Cigars, cheroots and cigarillos of tobacco or tobacco substitutes which have been exempt so far shall attract 16% CENVAT.

110. In view of the abolition of Administered Price Mechanism on petroleum products and in order to provide for the subsidy on LPG and kerosene oil, I propose to make some changes in the duty structure of petroleum products. The rate of cess applicable to indigenous crude oil under the Oil Industry (Development) Act will be increased from Rs 900 per metric tonne to Rs 1800 per metric tonne with effect from 1st March 2002. I propose to reduce the *ad valorem* rate of excise duty applicable to motor spirit from 90% to 32%. However, I propose to impose on it a surcharge of six rupees per litre. But the surcharge on ethanol doped motor spirit will be five rupees and twenty five paise per litre.

111. Mr. Speaker, Sir, the Indian textile industry occupies an important place in our economy. It is the second largest provider of employment after agriculture. The Multi Fibre Agreement will be phased out by 2004. Domestic market has already been opened up. Our textile industry has to prepare itself for the challenges ahead.

112. I have carved out a special package of incentives for the textile industry.

113. I propose to maintain the excise duty rates on yarns. At present, cotton hank yarn is exempt from excise duty but is being widely misused. In order to ensure that the benefit accrues only to the handloom weavers I propose to bring hank yarn within the net of excise duty at 8%, but at the same time, provide for appropriate subsidy on the price of hank yarn purchased by them. This will put an end to misuse and target the subsidy better. The Ministry of Textiles would announce the details of the subsidy scheme.

114. In order to enable the weavers to avail of CENVAT credit scheme, I propose to allow the weavers of grey fabrics to pay excise duty on an optional basis. I propose to extend a similar option to the knitting sector.

115. Mr. Speaker, Sir, in all humility, I can claim credit for introducing the CENVAT rate of 16% in the excise duty structure. However, in the case of textiles, I am making an exception and granting a remission of 4%. The rate of excise duty on fabrics, made ups and garments would be 12%. This special dispensation shall continue upto 28.2.2005. Industrial fabrics would however continue at 16%.

116. At present, hand processing of textile fabrics by independent processors is exempt from excise duty even if power is used on 12 specified processes in the case of cotton fabrics or 7 specified processes in the case of man made fabrics. I propose to confine this exemption to only 3 processes, namely, scouring, hydro-extraction and calendering.

117. I propose to abolish the compounded levy scheme for independent power processors as it is incongruous with the reduced rate of duty that I have proposed.

118. Handloom sector is not affected by my budget proposals. Excise duty exemption on handloom fabrics continues. I now propose to grant exemption to handloom garments also from excise duty subject to certification by Handloom Export Promotion Council.

119. In order to enable the textile industry to modernize itself and acquire new technology, I propose to exempt excise duty on automatic shuttleless looms. I also propose to exempt excise duty on specified processing machinery and specified silk reeling, weaving and twisting machinery. The customs duty on such machinery is also proposed to be reduced from 25% to 10%. I also propose to exempt specified jute machinery from excise duty. I hope this package will enable the textile industry to face global competition.

120. My proposals include special dispensation of excise duty structure for the petroleum refineries located in the North East Region. With effect from 1st March 2002, the petroleum products produced by all these refineries shall be charged to excise duty at half of the normal rates of excise duty otherwise applicable to petroleum products.

121. Inland Air Travel Tax is exempted for air travel within the North East States. I propose to extend this exemption on air travel to and from North East States.

122. Tea industry is currently facing a number of problems in the domestic as well as international markets for a variety of reasons. In order to promote the interest of tea growers, I propose to reduce the excise duty on tea from Rs 2 per kg to Re.1 per kg.

123. We have to face the menace of HIV-AIDS with determination. I propose to exempt specified anti-AIDS drugs from excise duty with effect from 1st March 2002.

124. Specified cold chain equipment are exempt from excise duty. I propose to add three more equipment to this list to promote the preservation of fruits and vegetables.

125. The excise duty exemption scheme for the small-scale sector is applicable to granite. In view of the fact that it is not available to marble, I propose to withdraw this exemption from granite also.

126. The scheme of excise duty assessment based on Maximum Retail Price of goods has resolved valuation disputes in a dramatic way. I propose to extend this scheme to 9 more categories of items this year, thus raising the number to 92 categories of items.

127. Mr. Speaker, Sir, the justification of taxing more services does not require any elaboration. This year, I propose to extend the service tax to the following services:

- ♦ Life insurance, including insurance auxiliary services relating to life insurance
- ♦ Inland cargo handling
- ♦ Storage and warehousing services (except for agriculture produce and cold storages)
- ♦ Event management
- ♦ Rail travel agents
- ♦ Health Clubs & Fitness Centres
- ♦ Beauty parlours
- ♦ Fashion designers
- ♦ Cable operators
- ♦ Dry cleaning services

128. Service tax is applicable to specified services provided by banks and non-banking financial companies. I propose to extend the service tax to corporate bodies that provide similar services.

129. The tax on these services shall come into force from a notified date.

130. Our tourism industry has been adversely affected by recent events. In December 2001, I had announced exemption from service tax on the services provided by hotels. The exemption expires on 31st March 2002. I propose to extend this exemption for one more year upto 31st March 2003.

131. Sir, I now present my proposals relating to customs duties.

132. The House may recall that, in my last budget, I had announced that I would move progressively to reduce the peak rate of customs duty to 20% within three years. I had also said that the modalities for this would be worked out in time for the next budget. I had accordingly set up an Inter-Ministerial Working Group to recommend the modalities. The Group has suggested a road map for this starting with this year's budget. After careful consideration of the Group's report, I have decided that, by the year 2004-05, there would be only two basic rates of customs duties, namely, 10% covering generally raw materials, intermediates and components and 20% covering generally final products. The existing rates would be adjusted and subsumed in these two

basic rates with some exceptions on account of WTO bindings or higher tariffs for agricultural products. In accordance with the road map, I propose to reduce the peak rate from 35% to 30% this year. I also propose to make some changes to take care of some current problems.

133. Our steel industry has been affected by slowdown in demand and has suffered large losses. In order to reduce its cost of production I propose to lower customs duty on a number of refractory raw materials by 10%. These include natural graphite powder, silicon metal, sintered alumina, fused zirconia and boron carbide. I also propose to reduce the duty on graphite electrodes of above 24 inches diameter from 25% to 15%.

134. Ships imported for breaking are charged to customs duty at 5% along with CVD and special additional duty. I propose to revise this by increasing the basic duty on ships for breaking from 5% to 15% and exempting them from CVD and special additional duty. This is to reduce the disparity between rolled products produced by the steel plants and cheaper products produced from ship breaking.

135. The steel industry is troubled by imports of seconds and defectives at cheaper prices. In order to address their concern I propose to increase the basic customs duty on seconds and defectives of steel to the bound rate of 40%.

136. Non-ferrous metals are used for large number of applications by different segments of industry. I propose to reduce the customs duty on copper, zinc and lead from 35% to 25% and on aluminium and tin from 25% to 15%.

137. In the EXIM policy for the year 2000-2001, my colleague, the Minister of Commerce and Industry announced the scheme of setting up Special Economic Zones that are intended to provide comprehensive facilities at one place for export production. Special Economic Zones would be entitled to procure duty free equipment, raw materials, components, etc. whether imported or purchased locally. The benefit of such exemption shall be applicable to both the developers of Special Economic Zones as well as the units located therein.

138. In order to encourage development of world class infrastructure facilities, I propose to reduce the customs duty on specified equipment for Ports and Airports to 10%.

139. In view of the difficulties being faced by the civil aviation sector, I propose to exempt duty on aeroplanes, helicopters, gliders, simulators of aeroplanes and their parts and raw materials.

140. Mr. Speaker, Sir, India is signatory to the Information Technology Agreement. The House may recall that, in 1998, I had announced that zero duty regime on IT products would be preponed and implemented by 2003. However, the local manufacturers have urged me strongly that it may be made effective only from the year 2005. This would give them an opportunity to gear up to meet the challenge of international competition. I have decided to accept their demand. As a further measure of assistance to indigenous industry, I propose to reduce the customs duty on a number of hardware inputs to 5%

and on certain capital goods to 15%. The duty on certain IT items would be reduced to 10% or 5% as per the WTO binding.

141. The use of cellular phones is increasing by leaps and bounds but import through unauthorized channels is a matter of concern. I therefore, propose to exempt cellular phones and pagers from CVD. The basic customs duty is, however, being increased from 5% to 10%.

142. Sir, I have repeatedly assured the House that our customs tariffs would be pegged at appropriate levels to protect the interest of the farmers. In my last budget I had increased the customs duty on tea, coffee, copra, coconut and desiccated coconut to 70%. This year, I propose to increase the customs duty on tea and coffee to 100% and on natural rubber, poppy seeds, pepper, cloves and cardamom to 70%. I also propose to increase the duty on pulses from 5% to 10%.

143. I propose to reduce the customs duty on agricultural machinery and implements from 25% to 15% to encourage our farmers to acquire new and efficient technology.

144. A number of drugs are exempt from customs duty. I propose to include eight more drugs used for treatment of cancer and some other critical diseases in the list of fully exempted drugs. Vaccine for immunisation against Japanese Encephalitis shall also be exempt from customs duty. It has been reported that certain drugs that are presently exempted from customs duty are now made indigenously. In order to provide reasonable incentive to the domestic manufacturers of these drugs, I propose to impose a basic customs duty of 5% on these drugs.

145. India has a large number of diabetic patients. They have to undergo frequent blood sugar tests. In order to provide some relief to them, I propose to reduce the customs duty on Glucometers and test strips from 25% to 10%.

146. As a measure of rationalization and removal of anomaly I propose to reduce the customs duty on non-PDS kerosene from 35% to 20% and increase the customs duty on kerosene sold under the PDS scheme from 5% to 10%.

147. In order to promote interest in science, I propose to reduce the customs duty on planetarium equipments, parts and accessories to 15% and also exempt them from CVD and special additional duty of customs.

148. India has the technical capability to become an uplinking hub for television channels for the SAARC countries. In order to promote state-of-the-art uplinking facilities at competitive costs, I propose to reduce customs duty on certain earth station equipment and studio equipment from 35% to 25%.

149. I propose to reduce the customs duty on cement and clinkers from 25% to 20%. This should help in keeping the domestic prices under control.

150. The customs duty on imported liquors is bound at 182% for the current year under the WTO. Accordingly, I propose to reduce the customs duty on these items from 210% to 182%. I also propose to rationalize the rates of CVD applicable to liquors and wines to 75% for value upto US \$ 25 per case and 50% for others.

151. Passengers returning from abroad on transfer of residence are allowed certain items of personal use on payment of customs duty at a flat rate of 35%. I propose to reduce this rate to 30% and also add a few more items like lap top computers, portable photocopy machines, digital video disc players, video cassette disc players in the eligible list of items. The overall limit is also being raised from Rs 1.5 lakh to Rs 5 lakh.

152. I propose to impose nominal customs duty of 5% on some of the items that are exempt at present. I also propose to impose special additional duty on certain other items that are currently subjected to 5% customs duty.

153. I have proposed a few other changes that are of a minor nature. I have also proposed some legislative changes with regard to customs, excise and service tax laws that are contained in the Finance Bill. I do not wish to take the time of the House in elaborating on them in detail.

154. Mr. Speaker, Sir, the customs and excise duty structures have been greatly simplified in the past few years. With the changes that I have proposed the revenue from 16% CENVAT will be more than 85% of the total revenue from *ad valorem* duties. In the next two years it can be reduced to one, namely 16%. The customs tariff will also comprise of only two basic rates in three years' time.

155. In my previous budgets, I have also made considerable efforts to simplify procedures. However, the task is not yet complete. Our tax administration needs to take full advantage of information technology. Our tax systems need to encourage voluntary compliance, provide efficient service to the taxpayers, eliminate unproductive work and enhance efficiency. The discretionary powers need to be replaced by rule-based mechanism. All these aspects of tax administration deserve to be examined in their entirety. I propose to set up an Expert Committee to make a comprehensive study of these aspects.

156. My proposals on the excise side are estimated to result in a revenue gain of about Rs 6700 crore in a year. On the customs side my proposals are estimated to result in a revenue loss of about Rs 2200 crore. However, I anticipate buoyancy in indirect tax revenue and estimate that the total collection next year would be Rs 1,43,702 crore.

157. Copies of the notifications issued to give effect to the changes in excise and customs duties shall be laid on the Table of the House in due course.

158. I now turn to Direct Taxes.

159. Personal Income tax rates have been at 10%, 20% and 30% and corporation tax at 35% for several years. They are reasonable and therefore, I have left them unchanged in my last four budgets. I do not propose to change them this year also.

160. At the same time, it is important to recognise the need for specific interventions to provide a stimulus for industrial growth. I outline these now.

161. I have already mentioned the need to provide incentives for fresh investments in the industrial sector. To give impetus to such investment, I propose to allow additional depreciation at the rate of 15% on new plant and machinery

acquired on or after 1st April, 2002 for setting up a new industrial unit, or for expanding the installed capacity of existing units by at least 25%.

162. There is disparity between the rates of Corporation tax applicable to foreign companies and domestic companies. This disparity arose in the past partly due to certain levies like surcharge being applicable to domestic companies but not to foreign companies. To correct this, I propose to reduce the rate applicable to foreign companies from 48% to 40%.

163. The small-scale industry sector has been making an important contribution to economic growth, and deserves continued support. In order to enable the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to augment its resources and provide cheaper credit to the small scale sector, I propose to allow capital gains exemption under section 54EC of the Income-tax Act to amounts invested in bonds issued by SIDBI.

164. In my Budget for 2000-2001, I had announced the setting up of a Credit Guarantee scheme for small-scale industries. Accordingly, the Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries has been constituted. I propose to grant full exemption from tax to the income of this Trust.

165. Continuing the thrust given to the housing sector over the last four years, I propose to allow the deduction for interest payable on housing loans for self-occupied houses even where such houses are acquired or constructed after 31st March 2003, as long as the acquisition or construction is completed within three years from the end of the financial year in which the loan was taken. For giving a further impetus to investment in the housing sector, I propose to extend the capital gains exemption provided in section 54EC of the Income-tax Act to bonds issued by the National Housing Bank.

166. The shipping industry in India is internationally competitive and is capable of further growth. In my Budget for 2000-2001, I had provided for a deduction of the entire profits of a shipping company if the amount deducted was kept in a reserve for purchase of new ships. However, the aggregate of the amounts that can be transferred to such reserve is limited to twice the amount of the paid up share capital of the company. I propose to extend it to cover share premium reserve and general reserve also. This reserve will not be considered while computing the book profits and shipping companies would thus be out of the purview of minimum alternate tax (MAT).

167. Presently, banks are allowed to deduct upto 5% of their total income against provisions made by them for bad and doubtful debts. In order to strengthen the financial position of banks I propose to increase this allowance to 7.5% of the total income. Further, in my budget for the year 1999-2000, I had granted an option to banks to deduct upto 5% of their NPAs falling in the category of loss or doubtful assets as on the last day of the accounting year. I propose to enhance this optional deduction to 10%, and also allow a similar option of deduction upto 10% of loss or doubtful assets to public financial institutions.

168. There has been a persistent demand that the benefit of carry forward and set off of past losses in cases of mergers of companies owning industrial undertakings, should be extended to more sectors. The telecommunication

sector, in particular, is undergoing a phase of rapid consolidation and expansion. With a view to encourage its growth, I propose to extend this benefit to companies providing telecom services and eligible for deduction under section 80-IA. I also propose to constitute an expert group to examine the extension of this benefit to other companies in the services sector, including the financial services sector.

169. In order to provide further fiscal relief to the tourism sector, I propose to take the following measures:-

- ❖ Expenditure Tax on hotels will, henceforth, apply only to room charges, and will be payable only where such charges are Rs 3,000 or more per day, as against the existing threshold of Rs 2000 per day.
- ❖ The deduction available under section 80HHD of the Income-tax Act in respect of foreign exchange earnings of hotels or tour operators will be enhanced to bring it in line with the deduction available to exporters under section 80 HHC.
- ❖ A deduction of 50% of the profits earned by units setting up and operating large convention centres will be allowed for 5 years under section 80-IB.

170. I have emphasised the importance of the entertainment industry in Part A of my speech. To give a further boost to this fast-growing sector, I propose to allow, for the next five years, a deduction of 50% of the profits earned by units constructing and operating multiplex theatres in non-metropolitan towns.

171. As a measure for protection and regeneration of our environment, I propose to provide for an incentive by way of tax deduction under section 35AC of the Income-tax Act in respect of amounts paid to a company or institution approved by the National Committee for Social and Economic Welfare, for carrying out projects of softwood plantation on degraded non-forest land. A deduction under this section will also be available in respect of payments towards conservation of natural resources and afforestation.

172. Last year, for ensuring a degree of transparency in the affairs of charitable and religious trusts as well as certain other institutions claiming exemption under section 10(23C), I had introduced provisions requiring them to publish their accounts in a local newspaper, if their total receipts during a year exceeded Rs 1 crore. I have received a large number of representations pointing out the possibility of misuse of such information by anti-social elements. In view of these representations, I propose to delete this requirement. I further propose to rationalise certain provisions relating to these trusts and institutions so as to allow the accumulation of any part of their income only upto a maximum period of five years and to clarify that inter-trust donations may only be made either from the corpus or from the current year's income.

173. Following the Gujarat earthquake last year, I had granted a 100% tax deduction to donations made to certain approved charitable trusts and institutions that were to be applied before 31st March 2002 in relief work. As such relief work is still going on in many areas, I propose to extend the terminal date for utilisation of such donations from 31st March 2002 to 31st March 2003.

174. Last year, I had rationalised the rules for valuation of perquisites on the basis of their cost to the employer, except in respect of houses and cars where different criteria are adopted for simplicity. To relieve the burden on lower salaried employees, I propose to provide that no perquisites will be assessed for the assessment year 2002-2003 in the case of employees whose taxable salary, excluding perquisites, is upto Rs 1,00,000. For subsequent years, I propose to give an option to the employer to pay the tax on perquisites on behalf of the employees.

175. Under section 89 of the Income-tax Act, a tax relief is provided in case of additional tax burden imposed in any one year due to receipt of arrears of salary. As a welfare measure, I propose to allow this relief also in cases where family pension is received in arrears.

176. In continuation with the taxpayer friendly measures brought about by me in my earlier Budgets, I propose to abolish the provisions of Chapter XXC of the Income-tax Act, which require a clearance to be obtained from the Appropriate Authority before registering a transfer of an immovable property.

177. Sir, some of the exemptions and deductions currently provided in the Income-tax Act have become redundant and are not in harmony with the moderate tax regime that we have in India. The Advisory Group on Tax Policy and Tax Administration for the 10th Plan has recommended deletion of a number of such exemptions. I have carefully examined each recommendation of the Group and have come to the conclusion that some of these exemptions are indeed unnecessary. I, therefore, propose to withdraw or discontinue the exemptions, which are not required any longer.

178. The Advisory Group has also recommended deletion of various exemptions granted to incomes of approved or notified bodies or institutions, including educational and medical institutions. I do not think that the exemptions allowed to these institutions and bodies, which are fulfilling social objectives, should be withdrawn. However, I propose to require all such bodies and institutions to file returns of income every year so as to enable a periodical verification of whether the prescribed conditions, which primarily relate to application of the income, are being fulfilled and also to enable the prescribed authority to withdraw the approval or notification of such entities if they are found to have violated any such conditions.

179. Last year, I had withdrawn the tax-exemption allowed to income earned by NABARD, National Housing Bank and SIDBI, since these institutions have come of age and are working on commercial lines. For the same reasons, I propose to withdraw this year the exemption allowed to income of the National Dairy Development Board, Prasar Bharati and the Oil Industry Development Board.

180. Various amendments made over the years in the rules relating to depreciation have given rise to a plethora of such rates for different types of assets. The relevance and the need to continue with these rates, and whether they should be scaled down to a maximum rate of 60%, should be a matter for open discussion. The relevant details will be put up on the website of the Finance

Ministry. After taking into account the views expressed, a revised schedule of depreciation rates will be notified.

181. Under the present system of taxation of dividends and income from units, the company or the mutual fund pays a 10% tax, and the income is exempt in the hands of the recipient. Such a system not only taxes income in the hands of a person to whom it does not belong; it also militates against the pass-through status which is the very essence of a mutual fund. There is also an inherent inequity in the present system, which allows persons in the high-income groups to be taxed at much lower rates than the rates applicable to them. These issues have been troubling me over the past four years, and I am now convinced that *the existing system must go. I, therefore, propose to abolish the distribution tax of 10% on companies and mutual funds on the dividends or income distributed by them. Such income will henceforth be taxed in the hands of the recipients at the rates applicable to them, and will be subject to tax deduction at source at the rate of 10%. In order to avoid a cascading effect, companies receiving such income will be entitled to claim a deduction for the amount in turn distributed by them as dividends. To continue the support given by me to equity oriented funds of the UTI and other mutual funds, the income received during the financial year 2002-2003 by unit holders of such funds will be taxed only at 10% as at present.*

182. A tax rebate of 20% of the amount invested in certain instruments specified in section 88 of the Income-tax Act is presently allowable to all individuals and HUFs, as an incentive for retaining a part of their earnings in the form of savings. Taxpayers in the higher tax brackets, however, do not require fiscal incentives to save through the various designated instruments. I therefore propose to allow the rebate at the existing rate of 20% only to persons having taxable income upto Rs 1,50,000. Persons having taxable income between Rs 1,50,000 and Rs 5 lakhs will henceforth get a rebate of only 10% of the amount invested, and no rebate will be allowed where taxable income exceeds Rs 5 lakhs. The special rebate of 30% for persons having taxable salary income upto Rs 1 lakh will, however, continue. Further, while the existing limits on the qualifying amounts of investment will remain, I propose to provide a clarification in the law that the rebate will be allowed on investments made at any time during the year, as long as the amount invested is less than the taxable income of the year.

183. Presently, tax exemption is available to certain categories of employees receiving amounts upto Rs 5 lakhs as VRS compensation. I propose to extend this exemption to employees of certain institutions of national or State-level importance to be notified in this behalf.

184. I am also making some procedural changes which are included in the Finance Bill.

185. A Scheme called "Sampark" is being launched by the Income Tax Department, which will enable taxpayers to obtain information and forms through the Internet. User-friendly software will be made available by the Department to enable taxpayers to prepare their returns of income.

186. Effective use of information technology will depend critically on strict compliance with the requirements relating to permanent account number (PAN). I propose to make a specific provision in the Income-tax Act for imposing a penalty of Rs 10,000 in all cases where a false PAN is quoted in documents relating to specified transactions.

187. In 1998, I had prescribed certain high-value transactions such as purchase or sale of motorcars and expenditure incurred in hotels and restaurants, in which the permanent account number is to be compulsorily quoted. I propose to extend this list of transactions provided in rule 114B of the Income-tax Rules to include expenditure exceeding Rs 25,000 incurred in cash on foreign travel, purchase of bank drafts exceeding Rs 50,000 in cash and making cash deposits exceeding Rs 50,000 in any bank account. I further propose to introduce rules to provide that any transaction specified in rule 114B which is incurred in cash must be reported within a certain period to the Income-tax Department.

188. Sir, I have already stated that national security is an overriding concern. Its cost has to be shared by all of us. I therefore propose to impose a modest surcharge of 5% across-the-board on all categories of taxpayers, except individuals and Hindu Undivided Families having total income upto Rs 60,000. The 2% surcharge imposed last year in the wake of the Gujarat Earthquake is being abolished and hence the net additional impact would be only 3%. I also propose to restrict the 100% deduction of export profits allowed to certain units under sections 10A and 10B of the Income-tax Act to a 90% deduction for the assessment year 2003-2004.

189. To sum up, Sir, my proposals made in this Budget on the Direct Taxes will result in a revenue gain of Rs 6,000 crore, including the component of surcharge of Rs 2,750 crore. I estimate that the direct tax revenue in 2002-2003 would be Rs 91,585 crore.

190. Mr. Speaker, Sir, with these proposals I estimate total tax revenue receipts for the Centre at Rs 1,72,965 crore and the fiscal deficit at Rs 1,35,524 crore or 5.3% of GDP.

191. Mr. Speaker Sir, this is a budget for consolidating, widening and deepening the reform process. This is a budget devoted to development. This is a budget to further promote partnership with the States for a better tomorrow for the people of India.

192. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the budget to this august house.

D. SWARUP. Addl. Secy.

